सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-33 अंक-2 | 22 जनवरी से 5 फरवरी, 2018 | मुख्य संपादक कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ 8 | मूल्य : 2 रुपये

22 अप्रैल1870 - 21 जनवरी1924

महान लेनिन जिन्दाबाद !

''... हमको इस बात पर गर्व करने का अधिकार है और हमको गर्व है कि यह हमारा सौभाग्य हुआ है कि हम सोवियत राज्य का निर्माण शुरू करें और उसके जरिये विश्व इतिहास में एक नये युग का, एक नये वर्ग के शासन के युग का श्रीगणेश करें –उस वर्ग के (शासन के युग का) जो हर पूंजीवादी देश में शोषित-पीड़ित है मगर जो हर जगह नयी जिन्दगी की तरफ, पूंजीपति वर्ग के ऊपर विजय की तरफ और मजदूर वर्ग के अधिनायकत्व की तरफ बढ़ रहा है–पूंजी के जुए से और साम्राज्यवादी युद्धों से मानव जाति की मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रहा है। ... पहली बोल्शेविक क्रान्ति ने इस पृथ्वी की पहली दस करोड़ जनता को साम्राज्यवादी युद्ध और साम्राज्यवादी दुनिया के शिकंजे से बाहर खींच लिया है। बाद की क्रान्तियां बाकी मानव जाति को ऐसे युद्धों से और इस दुनिया से बचायेंगी।''

(नवम्बर क्रान्ति की चौथी वर्षगांठ (1921) के अवसर पर दिये गए भाषण से)

''अपनी गलतियों की तरफ एक राजनीतिक पार्टी का रुख पार्टी की गंभीरता को और इस बात को जांचने की सबसे खास और सबसे पक्की कसौटी है कि वह अपने वर्ग की तरफ और मेहनतकश जनता की तरफ अपने कर्तव्यों को अमल में किस तरह पूरा करती है। अपनी गलती को खुलेआम मानना, उसके कारणों का पता लगाना, उसे पैदा करने वाली परिस्थियों का विश्लेषण करना और उसे सुधारने के तरीकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना–ये सब गंभीर पार्टी के लक्षण हैं; इसका मतलब अपने कर्तव्यों को पूरा करना होता है; इसका मतलब वर्ग को, और बाद में जनता को शिक्षित और प्रशिक्षित करना होता है।''

सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीशों की शिकायत ने खुलासा कर दिया कि सर्वोच्च स्तर की न्यायपालिका किस अभूतपूर्व गहन संकट में डूबी हुई है

–एसयूसीआई(सी)

एसयूसीआई (सी) के महासचिव, कॉ. प्रभास घोष ने 13 जनवरी, 2018 को निम्नलिखित बयान जारी किया :

सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने जल्दबाजी में बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में कथित गंभीर दुर्बलताओं, अनियमितताओं और प्रशासन में हस्तक्षेप के आरोप लगाए हैं कि किस तरह सर्वोच्च अदालत में भी मुकदमों की सुनवाई 'पसंदीदा' बैंचों को सौंपी जाती है। निचली अदालतों के न्यायाधीश बी.एच. लोया जो एक फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अभियुक्तों में से एक हैं, उनकी रहस्यमय ढंग से मौत के संबंध में उनके पत्र का जवाब न देने के भारत के मुख्य न्यायाधीश के फैसले का उन्होंने विशेष तौर से उल्लेख किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत के मुख्य न्यायधीश ने न्यायमूर्ति लोया की मौत के मामले में जांच की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई को टाल दिया। यह भी याद रहे कि न्यायमूर्ति लोया के परिवार वालों का आरोप है कि उनकी मृत्यु अप्राकृतिक थी और बीजेपी नेता के पक्ष में फैसला देने के लिए उन्हें 100 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश किये जाने के

(शेष पृष्ठ 3 पर)

अप्रतिरोध्य और अपराजेय है नवम्बर क्रांति का पैगाम

–प्रभास घोष

(गतांक से आगे)

एक सही कम्युनिस्ट पार्टी बनाने का लेनिनीय मॉडल

यही वह मार्क्सवाद था जिसे लेनिन ने प्रथम विश्वयुद्ध के बाद की प्रतिकूल परिस्थितियों में पूर्ण सफलता के साथ रूस में लागू किया। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि मार्क्स के समय में यह प्रश्न इतना अधिक नहीं उठा था कि एक सही कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कैसे किया जाए? मार्क्स ने केवल क्रांति का मार्ग निर्धारित किया था। अगला युग जैसा कि लेनिन ने दिखाया साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रांति का युग है। किसी भी देश में मार्क्सवादी पार्टी बनाने की प्रक्रिया के संदर्भ में विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन लेनिन ने मुहैया करवाया है। इसे हम पार्टी गठन का लेनिनीय मॉडल कहते हैं। लेनिन ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि एक मार्क्सवादी पार्टी महज एक सम्मेलन आयोजित करके या फरमान जारी करके गठित नहीं की जा सकती। उसके लिए एक विचारात्मक संघर्ष की आवश्यकता होती है, मार्क्सवादी विचारों और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के सामंजस्य की आवश्यकता होती है। पुरानी आरएसडीएलपी (रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी) भी रूस में मार्क्सवादी पार्टी के रूप में जानी जाती थी। लेकिन वह असली मार्क्सवादी पार्टी नहीं थी। लेनिन ने सबसे पहले आरएसडीएलपी के अंदर ही संघर्ष किया। मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आवश्यक एकता कायम करने के लिए 9 वर्षों तक कठिन संघर्ष करने के बाद उन्होंने बोल्शेविक पार्टी की स्थापना की। गैर-विभाजित सीपीआई ने भारत में उस संघर्ष को नहीं चलाया। वैचारिक एकता या सोच की एकरूपता कायम करने के संघर्ष को दरकिनार करते हुए बहुत सारे गुटों ने मिलकर रातोंरात पार्टी बना ली।

हालांकि उस समय के सीपीआई के नेता बहुत ईमानदार थे, लेकिन उन्होंने पार्टी निर्माण की लेनिनीय प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया। कॉ. शिवदास घोष ने लेनिन की अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाओं को आत्मसात किया और लेनिन की शिक्षाओं के आधार पर उन्होंने पार्टी बनाने की लेनिनीय प्रक्रिया को संवर्धित और

(शेष पृष्ठ 2 पर)

इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध

नई दिल्ली। इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा का देश की छः कम्युनिस्ट पार्टियों ने जमकर विरोध किया। एसयूसीआई (कम्युनिस्ट), भाकपा, भाकपा (माले), माकपा, कम्युनिस्ट गदर पार्टी ऑफ इंडिया, आर.एस.पी., सहित ऑल इण्डिया पैलेस्टाइन सोलिडेरिटी आर्गेनाइजेशन ने 15 जनवरी को इंडिया गेट के पास दिल्ली के शाहजहां रोड पर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। 'नेतन्याहू वापस जाओ' के नारे लगाकर प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध व्यक्त किया।

वक्ताओं ने इस्राइली प्रधानमंत्री के भारत आगमन के विरोध का कारण स्पष्ट करते हुए बताया कि किस तरह से इस्राइल

(शेष पृष्ठ 3 पर)

नई दिल्ली : इस्राइली प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए एसयूसीआई(सी) नेता कॉमरेड सत्यवान व साथ में अन्य वामदलों के नेता-कार्यकर्ता

कॉ. प्रभास घोष का भाषण

(पृष्ठ 1 का शेष)

विकसित किया और उसे समसामयिक भी बना दिया।

लेनिन ने बताया कि मार्क्स और एंगेल्स ने मार्क्सीय विज्ञान का आधार प्रस्तुत किया है और जो भी इसे विशिष्ट परिस्थितियों में लागू करेंगे, उन्हें इस विज्ञान को जीवन की बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार और भी विकसित और संवर्धित करना पड़ेगा। स्वयं लेनिन ने भी ऐसा ही किया। ऐसा ही माओ और स्टालिन ने भी किया। लेकिन भारत में किसी भी तथाकथित कम्युनिस्ट नेता ने यह संघर्ष करने का बीड़ा नहीं उठाया। यह कार्य केवल कॉ. शिवदास घोष ने ही किया था। उन्होंने मार्क्सवाद को और अधिक विकसित और संवर्धित किया था। लेनिन ने सीख दी थी कि अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा क्रांति की लाइन अलग-अलग देशों की अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग तरीके से लागू करनी होगी। उनके शब्दों में ''मार्क्स का सिद्धांत केवल एक सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करता है जिसे विशेष परिस्थितियों में विशेष रूप से लागू किया जाएगा। इसे इंग्लैण्ड में फ्रांस से अलग तरीके से, फ्रांस में जर्मनी से अलग तरीके से और जर्मनी में रूस से अलग तरीके से लागू किया जाएगा।'' (स्टालिन द्वारा 'लेनिनवाद के आधार' में उद्धृत) सामान्य नियमों को विशेष परिस्थितियों में विशेष तरीके से लागू किया जाएगा। कॉ. शिवदास घोष ने भारत में बिल्कुल वही कार्य किया और इस दौरान उस परिस्थिति की खास चारित्रिक विशेषताओं और उस परिस्थिति में आम लाइन को लागू करने की ठोस प्रक्रिया को भी उजागर किया। न तो अविभाजित सीपीआई और न ही बाद में सीपीआई(एम) ने ही इनमें से किसी कार्य को अंजाम दिया। लेनिन ने सिखाया था कि क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना क्रांति नहीं हो सकती। कॉ. शिवदास घोष ने इंगित किया था कि सिद्धांत कहने से लेनिन का तात्पर्य जीवन के तमाम पहलुओं को समेटे हुए आर्थिक-राजनैतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों के सिद्धांत से था। इसलिए एक क्रांतिकारी सिद्धांत को विकसित करने के लिए मार्क्सवाद को हर क्षेत्र में लागू करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से कॉ. शिवदास घोष ने लेनिन की शिक्षाओं को लागू किया था। लेकिन सीपीआई और सीपीएम ने भारत में ऐसा नहीं किया। इसलिए वे सामूहिक नेतृत्व और जनवादी केन्द्रीयता को लागू नहीं कर पाए। परिणामस्वरूप वे सही मायने में एक कम्युनिस्ट पार्टी का गठन नहीं कर पाए थे। इसलिए मार्क्सवाद का लबादा ओढ़े हुए वे यूरोप की अन्य सामाजिक-जनवादी पार्टियों की तरह ही पेटी बुर्जुआ पार्टियाँ ही बनकर रह गई। इसके अलावा, कॉ. शिवदास घोष ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद के ज्ञान-भण्डार में बहुत सारी चीजों का योगदान दिया है, जो आज की सभा में चर्चा का विषय नहीं है।

स्टालिन ने कैसे की समाजवाद की रक्षा और कैसे किया उसका विकास

लेनिन ने एक सही क्रान्तिकारी पार्टी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन (बोल्शेविक) का निर्माण किया। मार्क्सवाद को विकसित करते हुए उन्होंने इसकी समझदारी को नयी ऊँचाइयों तक पहुँचाया। स्टालिन ने बिलकुल ठीक बताया था कि लेनिनवाद ही साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रान्ति के युग में मार्क्सवाद है। लेनिन ने रूसी क्रान्ति की लाइन निर्धारित की और दिखाया कि यह मजदूर वर्ग के नेतृत्व में मजदूर-किसानों की एकता के आधार पर सफल की जाएगी। इस पर बहुत बहस हुई थी। ट्रॉट्स्की, जिनोवियेव, कोमनेव और बुखारिन ने यह कहते हुए लेनिन का विरोध किया कि एक देश में समाजवाद स्थापित नहीं किया जा सकता; न तो एक पिछड़े पूँजीवादी देश में क्रान्ति सफल की जा सकती है और न ही मजदूर-किसानों की एकता कायम की जा सकती। उन्होंने इस तरह के तमाम सवाल और विवाद उठाये। लेनिन ने उन सभी सवालों का जवाब दिया और तमाम भ्रान्तिजनक तर्कों का खण्डन किया। क्रान्ति के ठीक बाद, रूस बहुत ही बदहाल था। देश युद्ध से तबाह और अकाल से आक्रान्त था। दूसरी तरफ अठारह शक्तिशाली साम्राज्यवादी देशों ने बिना किसी चेतावनी के इसकी घेराबन्दी कर दी और आक्रमण कर दिया। ये आक्रमणकारी देश डैमोक्रेसी की बातें बघार रहे थे। लेकिन जिस तरह से इन्होंने रूस पर फौजी हमला किया, उसने दिखा दिया कि वे इस बात पर कटिबद्ध थे कि समाजवाद को फलने-फूलने न दिया जाए। क्योंकि वे जानते थे कि सोवियत समाजवाद उनके देशों पर भी निश्चित ही प्रभाव डालेगा। इन हालात में उनके देशों का भी मजदूर वर्ग भी क्रान्ति सफल करने के लिए संघर्ष छेड़ेगा। इसलिए उन्होंने नवजात सोवियत यूनियन को नेस्तनाबूद करने के इरादे से इस पर आक्रमण किया था। समाजवादी रूस की उस समय की विकट परिस्थितियों के बारे में जरा सोचिये। वह अन्दर से युद्ध और अकाल की वजह से तबाह था। देश के अन्दर उसके वर्ग-शत्रु गृहयुद्ध जारी रखे हुये थे। बाहरी तौर पर, वह साम्राज्यवादी भेड़ियों द्वारा किये जा रहे बिना उकसावे के संयुक्त फौजी हमले का सामना कर रहा था। ऐसी एक स्थिति में लेनिन की हत्या करने का प्रयास हो रहा था। उनको गोली लगने से वे बिस्तर पर थे। 1924 में उन्होंने अन्तिम सांस ली। रूस तब तक भी बहुत पिछड़ा हुआ देश था। उस समय बोल्शेविक पार्टी ने लेनिन के सुयोग्य शिष्य स्टालिन को सुप्रीम लीडर के रूप में चुना था। स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत समाजवाद के तीव्र विकास के लिए 1927 में पंचवर्षीय योजना लागू की गयी थी। जिन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आप इतना सुनते हैं, वे सोवियत यूनियन की ही देन हैं। पहली पंचवर्षीय योजना पूरी होने में पांच साल भी नहीं लगे। तीन साल के अन्दर ही सोवियत रूस बेरोजगारी से मुक्त हो गया था। प्रत्येक को काम मिल गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पूरी होने पर सोवियत यूनियन दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया था। महान स्टालिन के नेतृत्व में उसने ऐसा एक अनोखा मुकाम हासिल कर लिया था। यह कोई आसान काम नहीं था। बाहर से कोई मदद नहीं मिली थी। देश पर लगाये गये आर्थिक प्रतिबंध भी जारी थे। पार्टी के अन्दर ट्रॉट्स्की- बुखारिन-कामेनेव-जिनोवियेव गिरोह पार्टी-विरोधी गतिविधियाँ चला रहा था, लेनिन की शिक्षाओं को विकृत कर रहा था और कार्यकर्ताओं तथा लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा था। वर्ग द्रोहियों द्वारा उठाये गये तमाम सवालों का खण्डन करने के लिए कॉमरेड स्टालिन को सैद्धान्तिक जवाब देने पड़े। यह एक सैद्धान्तिक संघर्ष था जिसे उन्होंने पूरे जीवट और दृढ़निश्चय के साथ संचालित किया। साथ ही साथ उन्हें बाहरी आक्रमण का भी सामना करना पड़ा। स्टालिन के आह्वान पर समाजवाद को बचाने के लिए सोवियत यूनियन के कामगारों और किसानों ने वस्तुत: दिन-रात काम किया था। इस तरह सोवियत यूनियन दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गया था।

देश के अन्दर चल रहे षड़यंत्रों और बाहरी आक्रमणों से भी बढ़कर समाजवाद को कुचलने के लिए एक और साजिश रची जा रही थी। यह बहुत घातक थी। पार्टी की अग्रिम पंक्ति के एक नेता किरोव की लेनिनग्राद में पार्टी मुख्यालय के अन्दर गोली मारकर हत्या कर दी गयी। हत्यारे की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ करने पर पता चला कि एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। पार्टी के बहुत से नेता इसमें शामिल थे। अपने इस मनहूस इरादे में कामयाब होने के लिए साजिशकर्ताओं ने मिलिट्री और प्रशासन के अन्दर भी अपना नेटवर्क स्थापित कर लिया था। एक तरफ सोवियत यूनियन को तबाह करने के लिए इंग्लैण्ड, फ्रांस और अमेरिका जैसी साम्राज्यवादी महाशक्तियाँ हिटलर और मुसोलिनी की मदद कर रही थी। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के त्रिपुरी सम्मेलन में नेताजी सुभाष ने क्या कहा था। इसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, "तथाकथित जनतान्त्रिक ताकतें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन में समाजवाद को ध्वस्त करने के लिए षड़यंत्र कर रही हैं।" (क्रॉसरोड्स) गहरी चिंता के साथ उन्होंने यह कहा था। शुरूआती दौर में इन साम्राज्यवादी ताकतों ने हिटलर और मुसोलिनी की मदद की थी ताकि वे रूस को तबाह कर सकें। बुखारिन-कॉमेनेव-जिनोवियेव जैसे ट्रॉट्स्की के अनुयायी रूस को ध्वस्त करने में हिटलर के षड़यंत्र का हिस्सा बन गये। उन्होंने मिलिट्री और प्रशासन में एजेंटों को प्लांट कर दिया था। योजना यह थी कि किरोव के बाद, स्टालिन की हत्या कर दी जाएगी और तब हिटलर आक्रमण करेगा। इस दौरान वे भीतर से विद्रोह कर देंगे और सोवियत सरकार को गिरा देंगे ताकि जर्मनी रूस पर कब्जा कर सके। तब उन्हें सत्ता में बैठा दिया जाएगा। यह एक भयंकर साजिश थी सोवियत यूनियन को तबाह करने के लिए। इस प्रकार सत्ता से उखाड़ फेंके गये रूस के बुर्जुआ ने सोवियत समाजवादी सरकार को बेदखल करने के लिए घातक हमला बोला था। रूस में पूँजीवाद को पुन: स्थापित करने के लिए प्रतिक्रान्तिकारी उभार पैदा करने के लिए यह साजिश रची गयी थी। यह पृष्ठभूमि थी जिसमें मशहूर मास्को ट्रॉयल हुआ था जिसको केन्द्र करके स्तालिन के खिलाफ इतना निन्दा अभियान चलाया जाता है।

ऐतिहासिक मास्को ट्रॉयल

एक राजसत्ता का तख्ता पलटने का षड़यंत्र रचने के अभियुक्त व्यक्तियों पर मुकदमा गुप्त रूप से नहीं चलाया गया था। सोवियत यूनियन ने ऐसे अभियुक्तों पर खुली अदालत में मुकदमा चलाया था। उसने सभी देशों के राजदूतों के साथ-साथ जाने-माने वकीलों को भी मुकदमा देखने के लिए आमंत्रित किया था। छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्तों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। मैं सिर्फ एक व्यक्ति के नाम का उल्लेख करना चाहूँगा जो पूरी अदालती कार्रवाई के दौरान वहां उपस्थित था। वह था मास्को में अमेरिकी राजदूत जोसेफ डेविस। उन्होंने अपनी पुस्तक 'मिशन टू मास्को' में लिखा है कि ऐसा एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और पूरी तरह कानूनसंगत ट्रायल किसी दूसरे देश में नहीं हुआ है। निर्णायक साक्ष्यों, गवाहों के ब्यौरों और जिरहों के सामने एक के बाद एक अभियुक्त अपना गुनाह कबूल करने पर मजबूर हुए। डेविस ने यह भी कहा कि अभियुक्तों को देखने से किसी यातना या दमन का कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। ग्रेट ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध वकील डी.एन. प्रिट मुकदमा देखने के बाद साम्यवाद के प्रशंसक बन गये थे। ऐसा था मास्को ट्रायल। जो-जो मिलिट्री और प्रशासन में इस षड़यंत्र के ऐजेण्ट थे, उन्हें ट्रायल के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। जिनके बारे में सिद्ध हो गया कि उन्होंने गम्भीर अपराधों को अंजाम दिया है, उनको मौत की सजा दी गयी। इसी को आधार बनाकर बुर्जुआ मीडिया अभी भी स्तालिन के खिलाफ निन्दा अभियान चलाता है। उन्हें एक हत्यारा, कातिल और ऐसे ही अन्य विशेषणों से नवाजता है। लेकिन इस ट्रायल की सराहना तब रोमां रोलां, बर्नार्ड शॉ, आइन्स्टीन और ऐसी ही अन्य महान विभूतियों ने की थी। न तो रवीन्द्रनाथ टैगोर और न ही भारत की किसी अन्य ख्याति प्राप्त विभूतियों ने इस ट्रायल के खिलाफ कुछ कहा था। क्योंकि वे मुकदमे की न्यायसंगतता को समझ गये थे। वे सोवियत समाजवाद को तबाह करने के किसी षड़यंत्र का समर्थन नहीं कर सके।

साम्राज्यवाद ही है युद्ध का जनक और युद्धोन्माद में रहता है लिप्त

मैं पूछना चाहता हूँ, प्रथम विश्व युद्ध का षड़यंत्र किसने रचा था जिसमें लाखों लोग मारे गये, हजारों कस्बे और गांव खण्डहर में तब्दील हो गये? किसने किया समाजवाद ने या पूँजीवाद ने? किसने द्वितीय विश्व युद्ध को छेड़ा था जिसने लाखों निरीह लोगों की जान ले ली थी और इतनी तबाही मचायी थी। साम्राज्यवाद ही दोनों युद्धों के लिए जिम्मेदार था। मैं पूछना चाहता हूँ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी उपनिवेशों को लूटा और वहां स्वतंत्रता सैनानियों की हत्या किसने की? किसने उनको फांसी दी थी? साम्राज्यवाद ने दी। आगे मैं पूछना चाहता हूँ कि नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम किसने गिराया था जिसमें लाखों लोग मारे गये और लाखों ही आने वाली पीढ़ियों तक अपंग हो गये जबकि जापान आत्मसमर्पण के कगार पर था? अमेरिकी साम्राज्यवाद ने यह किया था। क्यों? क्योंकि चीन और कोरिया को आजाद कराने के बाद लाल फौज जापान की तरफ बढ़ रही थी। इसलिए उस बढ़त को रोकना था ताकि जापान लाल फौज के सामने नहीं, बल्कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने आत्म समर्पण करे। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जापान पर इस न्यूक्लियर बमबारी का परिणाम देखकर आइन्स्टीन को बड़ा भारी आघात लगा था। गहरी

(शेष पृष्ठ 4 पर)

हरियाणा में महिलाओं पर बढ़ते अपराधों का विरोध, सरकार के पुतले फूंके

नई दिल्ली । हरियाणा के कुरूक्षेत्र, पानीपत, जींद, पिंजौर और फरीदाबाद में हुए बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और निर्मम हत्याओं के खिलाफ 17 जनवरी को एआईएमएसएस, एआईडीवाईओ, एआईडीएसओ, एआईडीडब्ल्यूए, एआईयूटीयूसी आदि संगठनों ने नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पर संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर का पुतला फूंका।

प्रदर्शन को एआईएमएसएस की रीतु कौशिक, एआईडीडब्ल्यूए की आशा शर्मा, एआईडीवाईओ के गिरीश शर्मा और एआईडीएसओ के प्रशांत कुमार ने सम्बोधित किया।

रोहतक : कुरूक्षेत्र, जीन्द, पानीपत, फरीदाबाद व पिंजौर में एक ही दिन में हुए बलात्कार, सामूहिक बलात्कार व निर्मम हत्या जैसी जघन्य घटनाओं के खिलाफ 17 जनवरी को एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के कार्यकर्ता मानसरोवर पार्क में एकत्रित हुए और नेताजी सुभाष चौक पर प्रदर्शन कर भाजपा सरकार का पुतला फूंका।

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड सत्यवान ने कहा कि सरकार एक तरफ 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' का नारा लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में एक ही दिन में इतनी सारी सामूहिक बलात्कार व निर्मम हत्याएं जैसी घटनाएं हो रही हैं। इन जघन्यतम घटनाओं ने फिर साबित कर दिया है कि प्रदेश में छोटी-छोटी बच्चियां व महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। अपराधी कानून की कमजोरियों, पुलिस की ढीली करवाई के चलते छूट जाते हैं। यौन हिंसा और यौन-विकृत्ति ने विकराल रूप ले लिया है। हालात इस हद तक पहुंच गये हैं कि स्कूली बच्चियों समेत महिलाएं आंतक व असुरक्षा के साये में जीने पर मजबूर हैं।

पार्टी के जिला सचिव अनूप सिंह मातनहेल ने कहा कि प्रदेश में नशाखोरी, टीवी, फिल्मों व इंटरनेट पर अश्लील प्रचार ही समस्या के कारण हैं। उनमें से एक कारण घटता लिंगानुपात, भयंकर बेरोजगारी भी है। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। भाजपा सरकार महिलाओं को दोयम दर्जे की उपभोग की वस्तु समझने की सामंती मानसिकता, टीवी, फिल्मों, गानों व धारावाहिकों में महिलाओं को मनोरंजन की वस्तु के रूप में दिखाये जाने, गांव-शहरों में शराबखोरी, तमाम वेबसाइटों पर महिलाओं के अश्लील विज्ञापन, पोर्न साइटों पर प्रतिबंध लगाने की करवाई करने की बजाय उसे बढ़ावा देकर नौजवानों की मानसिकता को विकृत कर रही है। उन्होंने मांग की कि प्रदेश में महिला सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएं। बलात्कार व निर्मम हत्या जैसी घटनाओं की तुरंत जांच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

प्रदर्शन में हरीश कुमार, उमेश कुमार, राजकुमार समचाना, केशु काहनौर, जगदीश आदि भी मौजूद रहे।

गुरुग्राम : हरियाणा में जीन्द, पानीपत, पिंजौर, फरीदाबाद व गुड़गांव में लगातार हुए गैंगरेप व रेप के बाद हत्या की घटनाओं के खिलाफ 15 जनवरी को एआईडीवाईओ ने मुख्य डाकखाना चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला दहन कर रोष जताया। विरोध प्रदर्शन में काफी महिलाएं व युवा शामिल हुए।

प्रदर्शनकारियों को संगठन के जिला अध्यक्ष बलवान सिंह ने सम्बोधित किया। मीनाक्षी ने कहा कि शराबखोरी व अश्लीलता के चलते इस तरह की यौन अपराधों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। संगठन के जिला उपाध्यक्ष वजीर सिंह ने सरकार से मांग की कि इन भीषण अपराधों पर रोकथाम करने, पुलिस प्रशासन व न्यायिक मशीनरी को चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिए जरूरी कदम उठाये। अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दे। उन्होंने जोरदार सांस्कृतिक आंदोलन गठित करने का सभी से आह्वान किया।

तोशाम। हरियाणा में जगह-जगह बच्चियों और महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के खिलाफ यहां 17 दिसम्बर को ऑल इण्डिया किसान खेतमजदूर संगठन ने सिवानी चौक पर हरियाणा सरकार का पुतला दहन किया।

संगठन के भिवानी जिला सचिव कॉ. रोहताश सैनी ने कहा कि यौन हिंसा और यौन विकृत्ति ने भयावह रूप ले लिया है। स्कूली छात्राएं, बच्चियां और महिलाएं आर्तकित और असुरक्षित महसूस करती हैं। हाल ही में घटी घटनाओं ने सभी विवेकशील लोगों को हिला कर रख दिया है और अभिभावक बेहद चिंतित हैं। यौन हिंसा, यौन विकृत्ति के साथ-साथ महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक दुर्दशा चरम पर है लेकिन दुखदायी बात है कि सरकार बेखबर-सी है। इन घटनाओं की रोकथाम करने के लिए समाज में जो माहौल होना चाहिए वह नदारद-सा है। इसलिए लोगों का यह दायित्व बनता है कि जनआन्दोलन के दबाव से इस सरकार को अपनी प्राथमिकता बदलने पर मजबूर करें ताकि यह इन जघन्य अपराधों पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाये। वर्मा कमीशन की सिफारिशें तुरंत लागू करे।

इस अवसर पर नरसिंह बागनवाला, गोपीराम साहलावाला, उदयवीर धारवानबास, सुखबीर ढाणी माहू, राजकुमार रिवासा, नत्थु धारण, वजीर दुल्हेड़ी आदि भी उपस्थित थे।

दिल्ली : प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए कॉ. रीतु कौशिक

सुप्रीम कोर्ट के चार जजों की ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

बाद हुई थी। व्यथित जजों ने यह भी आरोप लगाया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का कोलेजियम एक गुट की तरह काम कर रहा है और कहा कि कोलेजियम के सदस्यों के बीच एक अदले का बदला जैसी व्यवस्था प्रचलित है। इस खुलासे से पूरा देश दहल उठा है कि न्यायपालिका कितने गहरे संकट से ग्रस्त है। जिस न्यायपालिका से लोग यह उम्मीद रखते हैं कि यह न्याय पाने का अन्तिम दरवाजा है, अगर वही न्याय के गर्भपात के द्योतक ऐसे चिंताजनक विवादों में उलझ जाएगी, तो ऐसे में इस पतनोन्मुख मरणासन्न नितांत भ्रष्ट पूंजीवादी व्यवस्था से लोग और क्या उम्मीद कर सकते हैं?

इससे एक बार फिर से पता चल गया है कि आर्थिक-राजनीतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन के हर क्षेत्र में सड़े-गले बदबूदार पूंजीवाद की दमघोंटू गिरफ्त और अध:पतन और पथभ्रष्टता से न्यायपालिका भी कतई मुक्त नहीं है। कार्य प्रक्रिया से इस तरह की छेड़छाड़ के खिलाफ और न्यायिक प्रणाली के इस अध:पतन पर रोक लगाने के लिए तुरंत शक्तिशाली संगठित जनमत विकसित करना अत्यावश्यक है। हम देश के लोगों का आह्वान करते हैं कि वे न्यायपालिका को इस तरह हाशिये पर डाले जाने के खिलाफ सम्मिलित जन प्रतिवाद का दबाव डालने के काम को अंजाम देने के लिए आगे आयें।

बेंजामिन नेतन्याहू वापस जाओ! ... ||

(पृष्ठ 1 का शेष)

लगातार फिलिस्तीनी जमीनों पर कब्जा जमा रहा है और फिलिस्तीनी जनता पर अत्याचार कर रहा है। माकपा के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉ. प्रकाश करात ने कहा कि भारत के साथ होने वाली सामरिक संधि से कमाए हुए पैसों का इस्तेमाल इस्राइल फिलिस्तीनी धरती का अतिक्रमण करने के लिए करेगा।

''हमने अभी तक करोड़ों रुपयों के हथियार इस्राइल से खरीदे हैं। इसी पैसे को इस्तेमाल करके इस्राइल सरकार फिलिस्तीनी जमीनों पर अपना कब्जा जमाए हुई है। इसलिए हम मांग करते हैं कि भारत सरकार इस्राइल सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सैन्य और सुरक्षा का रिश्ता कायम न रखे। हमें उनसे हथियार नहीं खरीदने चाहिए।'', प्रकाश करात ने कहा।

भाकपा के राष्ट्रीय सचिव ने अपने भाषण में इस्राइल की नीतियों का विरोध करते हुए कहा कि ''वे इस्राइल की सम्राज्यवादी नीतियों का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा, ''इस्राइल संयुक्त राष्ट्र शांति संधि की पेशकश को स्वीकार करने से लगातार इनकार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दो-राष्ट्र नामक समाधान पेश किया है। जहाँ फिलिस्तीन और इस्राइल दोनों का सह अस्तित्व होगा। इस्राइल भी रहेगा और फिलिस्तीन भी रहेगा। परंतु इस्राइल इसे स्वीकार नहीं करता है हम इस्राइल की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। इजराइल लगातार फिलिस्तीनी धरती पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करता जा रहा है। इस्राइल लगातार फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ युद्ध छेड़ता जा रहा है। फिलिस्तीनी जनता आजादी और एक आजाद मुल्क की स्थापना के लिए संघर्ष कर रही है। भारत एकमात्र पहला गैर-अरबी मुल्क है जिसने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी है।''

इस्राइल-फिलिस्तीनी संकट पर बात रखते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉ. सत्यवान ने फिलिस्तीनी जनता का समर्थन किया और यरूशलम को इस्राइल की राजधानी घोषित करने के अमेरिकी कदम का विरोध किया। उन्होंने कहा, ''हम फिलिस्तीनी जनता के संघर्ष को जायज मानते हैं। हाल में अमेरिका के द्वारा यरूशलम को इस्राइल की राजधानी घोषित करना अन्यायपूर्ण है तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ भी है।''

उन्होंने आगे कहा, ''भारत की परंपरा साम्राज्यवाद के खिलाफ रही है। भारत की जनता साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ी है। भारत ने अपनी आजादी खुद लड़कर हासिल की है। भारत दुनिया भर में शांति का पक्षधर रहा है। लेकिन मोदीजी भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं बल्कि उंगलियों पर गिने जाने लायक कुछ बड़े पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।''

कॉ. प्रभास घोष का भाषण

(पृष्ठ 2 का शेष)

व्यथा-वेदना के साथ उन्होंने कहा था, 'मेरे पुनर्जन्म पर एक वैज्ञानिक के रूप में मेरा जन्म न हो, यदि हो, तो मैं एक बढ़ई होना चाहूँगा। ओह विज्ञान का इतना दुरुपयोग! यह निर्मम जनसंहार किसने किया था? साम्राज्यवाद-पूँजीवाद ने किया था। फासिस्ट हिटलर ने लाखों बेगुनाह यहूदियों और कम्युनिस्टों का कत्ल किया था। क्या पूँजीपति वर्ग के टुकड़खोर बुद्धिजीवी और मीडिया इन तमाम बातों पर चर्चा करते हैं? क्या वे इस पर कोई सवाल उठाते हैं? वियतनाम के लोग अपने देश को आजाद कराने के लिए पहले फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़े और फिर जापानी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़े थे। उसके बाद अमेरिकी साम्राज्यवाद ने वियतनाम के मुक्ति-संघर्ष को कुचलने के लिए घातक नापाक बमों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। इससे बड़ा जघन्य अपराध और क्या हो सकता है? हाल ही में एक कपटपूर्ण बहाना बना कर कि सद्दाम हुसैन के पास जनसंहारक हथियार हैं, किसने इराक को तबाह किया है? अब तक सिद्ध हो गया है कि यह एक पूर्णत: झूठा आरोप था। लीबिया और अफगानिस्तान को किसने तबाह किया है? तालिबानियों, अल कायदा और आईएसआईएस को पैदा करने वाला कौन है? उन्हें हथियार कौन मुहैया करा रहा है? जग जाहिर है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद। अमेरिकी साम्राज्यवादी धार्मिक आतंकवाद के जन्मदाता हैं। अब वे सीरिया के खिलाफ छद्म युद्ध चला रहे हैं। तथाकथित 'निष्पक्ष' मीडिया और हमारे देश के साथ-साथ दुनियाभर के बिकाऊ स्तम्भकार अमेरिकी साम्राज्यवाद के तमाम ऐसे जघन्य कृत्यों पर क्यों रहस्यमय चुप्पी साधे हुए हैं? लेकिन वे जब तब स्टालिन के खिलाफ झूठे आरोप लगाते रहते हैं और उन्हें बदनाम करते हैं। इतिहास इन्हें माफ नहीं करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया स्टालिन और सोवियत यूनियन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती थी कि हिटलर और मुसोलिनी के फासीवादी आक्रमण से दुनिया को सिर्फ स्टालिन ही बचा सकते हैं। स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत यूनियन ने उनकी उम्मीदों को पूरा किया। लाल फौज ने सारे पूर्वी यूरोप को मुक्त किया जहां समाजवाद स्थापित हो गया था। उस समय, सोवियत यूनियन ने सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण और तमाम सामरिक संधियों को निरस्त करने का आह्वान किया था, जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। उसने कहा था कि वह इसके लिए तैयार है। आइये दुनिया को युद्ध की विभीषिका से मुक्त कर दें। यह स्टालिन का आह्वान था।

स्टालिन जुझारू-शान्ति आन्दोलन गठित कर रहे थे। लेकिन उसी समय सोवियत यूनियन की घेराबन्दी करने के लिए साम्राज्यवादियों ने नाटो और सियेटो जैसे गठबन्धन बनाने शुरू कर दिये थे। इन हालात में आत्मरक्षा के लिए सोवियत यूनियन को वारसा संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। यह इतिहास है।

स्टालिन थे लेनिन के सुयोग्य छात्र

स्टालिन पार्टी क्रिया कलापों और राजसत्ता के संचालन का काम मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन की शिक्षाओं के अनुसार करते थे। जिन तमाम विदेशियों ने उन्हें देखा और मिले वे सभी उनसे बहुत प्रभावित होते थे। वे बहुत ही सरल और विनम्र थे। वे हमेशा अपने को लेनिन का शिष्य बताते थे। यदि कोई कहता कि वह स्टालिन का शिष्य है, तो वे तुरन्त प्रतिवाद करते। वे कहा करते थे कि मैं खुद जब लेनिन का छात्र हूँ, तब कैसे कोई मेरा शिष्य हो सकता है? उन्होंने इसे हमेशा बरकरार रखा। वे कहा करते थे : मैं पार्टी की, मार्क्सवाद-लेनिनवाद की उपज हूँ। यदि मेरा कोई गुण है तो वह मार्क्सवाद-लेनिनवाद और सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की देन है। चर्चिल उनसे मिलने गये थे। वे यह देखकर हैरान हो गये कि स्टालिन ऐसे कमरे में रहते थे जो ठीक वैसा ही था जैसा ब्रिटेन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए होता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सके। सोवियत यूनियन में अमेरिकी राजदूत डेविस ने अपनी बेटी को लिखा था, "अगर आप एक व्यक्तित्व का खाका खींच सको जो ठीक उसके विपरीत हो, जो घोर स्टालिन-विरोधी प्रचारित करते हैं, तब आप इस आदमी (स्टालिन) की तस्वीर बना सकती हो। ...कोई भी बच्चा उनकी गोद में बैठना चाहेगा।" (मिशन टू मास्को) उस समय के एक जाने-माने पत्रकार जॉन गुन्थर ने टिप्पणी की थी, "संगी-साथी हिटलर की पूजा करते थे, मुसोलिनी से डरते थे और स्टालिन का आदर करते थे। यही इसका सार प्रतित होता है।" (स्टालिन-हारपर मैगजीन में प्रकाशित एक लेख) बर्नाड शॉ ने एक बार पूछा कि उनके मतानुसार किस देश में असल आजादी कायम है। उन्होंने उत्तर दिया, "दुनिया में सिर्फ एक देश है जहाँ आप आजादी का लुत्फ उठा सकते हैं- वह है रूस जहां मार्शल स्टालिन अभी भी जिन्दा हैं।" (नये राजनेता और राष्ट्र, दिसम्बर, 1934) रोमां रोलां ने कहा था कि जब तक वे जिन्दा रहेंगे, स्टालिन सोवियत यूनियन के लिए काम करेंगे। इस महान मानवतावादी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "मास्को डायरी" में दर्ज किया "जैसा कि देख रहे हैं कि स्टालिन ने रूस के इतिहास में और दुनिया के लोगों के लिए क्लासिकल युग का एक नया अध्याय खोल दिया है।" जब 1945 में आजाद हिन्द फौज युद्ध में हार गयी थी तब सिंगापूर रेडियो से प्रसारित अपने भाषण में गहरी श्रद्धा और पूरे आत्मविश्वास के साथ नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने कहा था, "युद्धोपरांत यूरोप में सिर्फ एक ही शक्ति है जिसके पास एक योजना है जो आजमाने लायक है और वह शक्ति है सोवियत यूनियन। आज यूरोप में अगर कोई एक आदमी है जिसके हाथ में अगले कुछ दशकों तक यूरोपीय राष्ट्रों का मुस्तकबिल है, तो वह आदमी मार्शल स्टालिन है।" जिन महान हस्तियों ने सोवियत यूनियन और स्टालिन की प्रशंसा की थी, उनमें से कोई भी कम्युनिस्ट नहीं था।

स्टालिन बहुत ही सादा जीवन जीते थे। उनके अंगरक्षक अलैक्सी रीबिन ने अपने संस्करण में लिखा था कि स्तालिन के पास तीन या चार से ज्यादा पोशाकें नहीं थी। यदि उनका कोट फट जाता था तो वे उसे सिलवा लेते थे। उनके स्तर का एक राजनेता और लीडर ऐसा एक सीधा-साधा जीवन जीता था। वे एक मजदूर के बेटे थे और एक मजदूर की तरह ही जीवन जीते थे। हम जब स्कूली छात्र थे तब दूर दराज के गांवों में भी स्तालिन के बारे में चर्चा होती थी। प्रत्येक घर में दो नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिये जाते थे – सुभाष और स्टालिन।

आप जानते हैं कि अपनी फांसी से ठीक पहले भगत सिंह ने ये नारे बुलन्द किये थे-"मार्क्सवाद-जिन्दाबाद", "इंकलाब जिन्दाबाद'', ''सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद-जिन्दाबाद"। उन्होंने मार्क्सवाद को अपनाया था। नेताजी सुभाष ने एक क्रान्तिकारी नेता बारेन घोष को लिखा था कि भारत का भविष्य का उद्देश्य है साम्यवाद स्थापित करना। वे सभी सोवियत यूनियन की शानदार उपलब्धियों और स्टालिन जैसे एक महान कम्युनिस्ट नेता को देखकर कम्युनिज्म के प्रति आकर्षित हुए थे। पूँजीपति वर्ग द्वारा स्टालिन के खिलाफ आक्रमणों की झड़ी लगा देना असल में मार्क्सवाद-लेनिनवाद, सर्वहारा क्रान्ति और सामाजिक प्रगति पर हमला है। क्योंकि स्टालिन अभी भी इन सबके जीवंत प्रतीक हैं। हम जानते हैं कि झूठ कुछ समय तक लोगों को भ्रमित कर सकता है लेकिन लम्बे समय तक नहीं। पहले ही पता चल रहा है कि रूस में साथ ही साथ पूरी दुनिया में स्टालिन अपना सम्मानित स्थान फिर से हासिल कर रहे हैं।

समाजवाद कर देगा हमेशा के लिए मानव द्वारा मानव के शोषण का खात्मा

रूस की सरजमीं पर मार्क्सवाद को सही-सही और रचनात्मक तरीके से लागू करते हुए सोवियत समाजवाद ने मानवजाति के इतिहास में एक शानदार नया अध्याय जोड़ा है। यह भी सच है कि प्रतिक्रान्तिकारी उभार की वजह से सोवियत समाजवादी समाज अब अस्तित्व में नहीं रहा है। हम दुखी हैं लेकिन निराश-हताश नहीं हैं। इतिहास की सीखों से मैं एक तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। प्रत्येक नये आदर्श या आन्दोलन को अन्तिम विजय प्राप्त करने के लिए पराजयों और विजयों, सफलताओं और विफलताओं के चक्र से गुजरना पड़ा है। धार्मिक आन्दोलनों का दावा था कि उनकी ताकत दैवी शक्ति में निहित है। लेकिन किसी भी धार्मिक आन्दोलन ने एक झटके में फतह हासिल नहीं कर ली थी। ईसाइयत, इस्लाम, हिन्दू धर्म और बौद्ध धर्म के लिए भी यही सच था। हालांकि बुद्ध भगवान में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने सिर्फ एक विचारधारा को प्रचारित किया था। बुद्ध की विचारधारा, हिन्दू धर्म के वेदान्त दर्शन और तमाम धर्मों के प्रसार में जीत और हार का एक चक्र सैकड़ों साल चला था तब जाकर उन्हें लोगों की मान्यता मिली थी। यह इतिहास है। हम जिसे बुर्जुआ डैमोक्रेसी या संसदीय डैमोक्रेसी कहते हैं, उस पर भी यही बात लागू होती है। पुनर्जागरण 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और संसदीय डैमोक्रेसी अंतत: 18वीं शताब्दी के उतरार्ध और 19वीं शताब्दी के शुरू में ही अपनी जड़ें जमा सकी थी। अन्तिम विजय हासिल करने में इसे साढ़े तीन सौ साल लग गये थे। पुनर्जागरण का दौर पार होने के बाद कहीं संसदीय व्यवस्था कायम हुई थी और एक बार राजतंत्र पुन: स्थापित हो गया था। लेकिन दोबारा फिर संसदीय व्यवस्था वापस आ गयी थी। अगर आप फ्रांस और इंग्लैण्ड के इतिहास का अध्ययन करेंगे, तो आपको संसदीय जनतंत्र की स्थापना के इतिहास के उतार-चढ़ाव के बारे में पता चलेगा।

धार्मिक आन्दोलन दमन-उत्पीड़न के खात्मे के लिए आन्दोलन नहीं थे। दमन-उत्पीड़न के एक स्वरूप की जगह दूसरा आ गया था। गुलाम व्यवस्था की जगह राजतंत्र ने ले ली थी। फिर बुर्जुआ संसदीय व्यवस्था कायम करने के लिए सामंती-राजतंत्रीय शासन को उखाड़ फेंका गया, यह भी पूँजीवादी शोषण पर आधारित है। लेकिन समाजवाद आया है हजारों वर्षों से जारी मानव द्वारा मानव के शोषण का सदा-सदा के लिए खात्मा करने की खातिर। इसका मायने है कि समाजवाद को हजारों सालों के दमनात्मक शासन के खिलाफ लड़ना होगा। हजारों सालों के मुकाबले 70 साल कुछ भी नहीं है। आपको इसे समझना चाहिए।

तमाम मार्क्सवादी हस्तियों ने प्रतिक्रान्ति की संभावना के बारे में किया था आगाह

इस सम्बंध में मैं विश्व साम्यवादी आन्दोलन के महान शिक्षकों और मार्गदर्शकों की अमूल्य शिक्षाओं में से कुछ आपके सामने रखना चाहूंगा। साम्यवाद की प्रथम अवस्था के रूप में समाजवाद की व्यख्या करते हुए महान मार्क्स ने कहा था, "यहां हमारा वास्ता उस साम्यवादी समाज से नहीं है, जो अपनी ही बुनियादों पर विकसित हुआ है, बल्कि, इसके विपरित, उससे है, जो पूँजीवादी समाज से उदित हो रहा है; इस कारण जो आर्थिक, नैतिक और बौद्धिक, हर मानी में अभी भी उस पुराने समाज के जन्म चिन्ह लिए हुए है, जिसके गर्भ से वह पैदा हुआ है।" (गोथा कार्यक्रम की आलोचना) मार्क्स की इस शिक्षा के मुताबिक पूँजीवाद का आर्थिक, नैतिक और बौद्धिक प्रभाव समाजवाद में भी रहता है। उन्होंने आगे सिखाया, ''कम्युनिस्ट समाज की उच्चतर अवस्था में, व्यक्ति की श्रम विभाजन के प्रति दासत्वपूर्व अधीनता और उसी के साथ-साथ मानसिक और शारीरिक श्रम के बीच का अन्तर्विरोध विलुप्त हो जाने के बाद, श्रम जीवन का मात्र एक साधन ही नहीं, बल्कि जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता बन चुकने के बाद; व्यक्ति के सामाजिक सम्पदा के सभी स्रोतों के अधिक वेग से प्रवाहमान होने के बाद-इनके बाद ही कहीं जाकर पूंजीवादी अधिकार के संकीर्ण क्षितिज को पूर्णत: लांघा जा सकेगा और समाज अपनी पताका पर अंकित कर सकेगा : ''प्रत्येक से उसकी क्षमतानुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुसार!'' (वही) इसका मतलब है, जब तक समाजवाद में उपरोक्त परिवर्तन नहीं हो जाते, तब तक पूंजीवादी अधिकार की धारणा बनी रहती है। मार्क्स की यह चेतावनी थी। मार्क्स ने आगे कहा था : ''पूंजीवादी और साम्यवादी समाज के बीच एक के दूसरे में क्रान्तिकारी रूपान्तरण का काल है।''(वही) मार्क्स ने इसे सर्वहारा का क्रान्तिकारी अधिनायकतत्व कहा था। इस ऐतिहासिक कथन के अनुसार अगर इस कालावधि में अर्थात् समाजवाद में सही क्रान्तिकारी रास्ते का अनुसरण किया जाता है, तो साम्यवाद को हासिल किया जा सकता है। अगर क्रान्तिकारी रास्ते से भटकाव हुआ, तो पूंजीवाद की पुनर्स्थापना हो जाएगी।

महान लेनिन ने 1919 के बाद इस बारे में आगाह किया था। उनके शब्दों में, ''सिद्धांत की दृष्टि से, इसमें

(शेष पृष्ठ 5 पर)

कॉ. प्रभास घोष का भाषण

(पृष्ठ 4 का शेष)

कोई सन्देह नहीं हो सकता कि पूंजीवाद और कम्युनिज्म के बीच एक निश्चित संक्रमण-काल होता है। इस काल में यह हो ही नहीं सकता कि सामाजिक अर्थव्यवस्था के इन दोनों ही रूपों की चारित्रिक विशेषताएं और गुण-धर्म घुले-मिले न हों। यह संक्रमण-काल मरणोन्मुख पूंजीवाद और विकासोन्मुख कम्युनिज्म के बीच, या दूसरे शब्दों में, जो पराजित हो चुका है, पर अभी नष्ट नहीं हुआ है उस पूंजीवाद और उस कम्युनिज्म के बीच संघर्ष का काल ही हो सकता है, जो पैदा हो चुका है, पर अभी बहुत कमजोर है। ... सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतत्व के युग में वर्ग बाकी हैं और बाकी रहेंगे।'' (सर्वहारा के अधिनायकतत्व के युग की अर्थनीति तथा राजनीति) उन्होंने आगे यह भी कहा था : ''शोषकों को चकनाचूर तो कर दिया गया है, पर वे अभी नष्ट नहीं हुए हैं। उस अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी के रूप में उनके पास अब भी एक अन्तर्राष्ट्रीय आधार मौजूद है, जिसकी एक शाखा का वे प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके पास अब भी उत्पादन के कुछ साधनों का एक भाग है, उनके पास अब भी पैसा है, उनके सामाजिक सम्बन्ध अब भी बहुत विस्तृत हैं। चूंकि वे पराजित हो चुके हैं, ठीक इसीलिए उनके प्रतिरोध की स्फूर्ति सौगुनी, हजारगुनी बढ़ गई है। राजकीय, सैनिक और आर्थिक प्रशासन की ''कला'' उन्हें वरिष्ठता प्रदान करती है, जिसकी वजह से उनका महत्व जनसंख्या में उनके अनुपात को देखते हुए अतुलनीय रूप से अधिक है। शोषितों के विजयी हिरावल दस्ते अर्थात् सर्वहारा वर्ग के खिलाफ सत्ता से उखाड़ फेंक दिये गए शोषकों द्वारा चलाया जाने वाला वर्ग-संघर्ष अतुलनीय रूप से अधिक कटु हो गया है...।''(वही) उन्होंने 1920 में यह भी कहा था, ''सर्वहारा का अधिनायकतत्व वास्तव में एक बहुत ही कठिन और निर्मम युद्ध है, जो एक नया वर्ग अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ चलाता है। इस शत्रु की पराजय से (भले ही वह केवल एक देश में पराजित हुआ हो) उसका प्रतिरोध दस-गुना बढ़ जाता है, और इस शत्रु की शक्ति सिर्फ अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी की शक्ति में ही निहित नहीं है, इसकी ताकत पूंजीपति वर्ग के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की ताकत और मजबूती में ही नहीं पायी जाती, बल्कि वह आदतों की ताकत में भी पायी जाती है; उसकी शक्ति छोटे पैमाने के उत्पादन की शक्ति में भी निहित है।'' ('वामपंथी कम्युनिज्म' एक बचकाना मर्ज) सर्वहारा वर्ग का अधिनायकतत्व पुराने समाज की शक्तियों और परम्पराओं के खिलाफ ऐसा अनवरत संघर्ष है, जो खूनी और रक्तहीन, हिंसापूर्ण और शांतिमय, सैनिक और आर्थिक, शिक्षा-सम्बन्धी और शासन-सम्बन्धी – अनेक रूप धारण करता है। लाखों लाख इन्सानों की आदत की ताकत एक भयंकर ताकत होती है।'' (वही) यहाँ यह उल्लेख करना संगत है कि पराजित पूंजीपति वर्ग की बात के अलावा, लाखों करोड़ों लोगों में पुराने समाज की आदतों और परम्पराओं की ताकत से लेनिन का तात्पर्य था जनता में बुर्जुआ (पूंजीवादी), निम्न-पूंजीवादी और सामन्ती मानसिकता, संस्कृति और आदतें और इस ताकत को उन्होंने पूंजीवाद की हिमायती एक खतरनाक ताकत माना था। यह समझ लेना होगा कि जब तक शोषित-पीड़ित जनता मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारों से सुशिक्षित नहीं कर दी जाती, तब तक वह शोषण से मुक्ति की चाह से संचालित होकर क्रान्ति के पक्षधर होने के बावजूद, आदत की ताकत के रूप में इन सब नुकसानदेह विचारों के जहरीले प्रभाव में रहेगी। नेतत्व को इससे खबरदार रहना चाहिए और ऐसे नुकसानदेह विचारों के खिलाफ तीव्र वैचारिक-सांस्कृतिक संघर्ष चलाना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता-कार्यकर्ताओं के बीच भी स्तर का अन्तर है। जो इस संघर्ष में पिछड़ जाते हैं उनमें ये ताकतें सूक्ष्म रूप से काम करती हैं। अत: पूंजीवादी और सामन्ती चिंतन और संस्कृति के इन सब अवशेषों को दूर करने के लिए सचेत संघर्ष चलाना निहायत जरूरी है।

महान स्टालिन ने सीपीएसयू की 17वीं कांग्रेस में भी कहा था कि समाजवाद जितना अधिक उन्नत होता जाता है, वर्ग संघर्ष उतना ही और अधिक तीव्र होता जाता है। उन्होंने गहरी चिंता के साथ बार-बार बताया था कि कई नेता और कार्यकर्ता वैचारिक संघर्ष को यथोचित महत्व नहीं दे रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब दुनिया भर में सभी स्टालिन की वाहवाही कर रहे थे, लोग समाजवाद के बारे में उत्साहित थे और युद्ध से तबाह सोवियत अर्थव्यवस्था पुनर्निर्माण के माध्यम से फिर से शक्तिशाली बन गई थी, तब स्टालिन ने सीपीएसयू की 19वीं कांग्रेस में बहुत चिंता व्यक्त की थी, जो उनके निधन से कुछ दिनों पहले ही आयोजित हुई थी। उन्होंने इससे पहले जब बहुत गंभीर संकटों से रूबरू थे, तब भी इतनी चिंता व्यक्त नहीं की थी। उन्होंने कहा था, ''जीत के साथ युद्ध के समापन और युद्ध के बाद से आर्थिक क्षेत्र में हमारी बड़ी-बड़ी उपलब्धियों के साथ ... हमारी पार्टी पांतों के सदस्यों में आत्म संतुष्टि की प्रवृत्ति ... एक आत्मसंतुष्टता की भावना घर कर गई है। ... काफी संख्या में जिम्मेदार कार्यकर्ता ...यह सोचने की ओर प्रवृत्त हो गए हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे वश से बाहर कुछ भी नहीं है, ... सब ठीक-ठाक चल रहा है और उनके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ... बैठकों, सभा-सम्मेलनों ... प्लेनरी मीटिंगों और कान्फ्रेंसों को वे आत्म प्रशंसा के दिखावा भरे प्रदर्शन में तब्दील कर देते हैं ...ये नौकरशाही और अध:पतन की भद्दी विशेषताएं हैं ... हमारे कार्यकारी अधिकारियों में से कुछ ... कर्मियों का चयन का अपना आधार .. . रिश्तेदारी, दोस्ती और गृहनगर संबंधों पर आधारित रखते हैं ... (वहां) मामलों की असलियत छिपाई जाती है .. . और परिणामों का चित्रण ... बहुत गुलाबी रंगों में किया जाता है ...पार्टी के और राजकीय अनुशासन का सबसे खतरनाक और शातिराना उल्लंघन किया जाता है। (*सीपीएसयू की 19वीं कांग्रेस की रिपोर्ट*) उन्होंने गंभीर चिंता के साथ यह भी कहा था : ''... हमारे अन्दर अभी भी बुर्जुआ विचारधारा के अवशेष हैं, निजी संपत्ति, मानसिकता और नैतिकता के बचे-खुचे अवशेष हैं। ये अवशेष खुद-ब-खुद मर नहीं जाते हैं; वे बहुत दृढ़ता से चिपके रहने वाले होते हैं और अपनी पकड़ मजबूत बनाये भी रख सकते हैं। ... पार्टी के वैचारिक काम को उन लोगों के दिमाग को शुद्ध करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए जिनमें पुराने समाज से विरासत में मिली पूंजीवादी मानसिकता, पूर्वाग्रहों और संक्रमित परंपराओं का अस्तित्व बचा हुआ है।'' (वही) हमें यह समझ लेना है कि आदत और परंपरा की शक्तियां जिसके बारे में लेनिन ने 1919-20 में चेतावनी दी थी, समाजवाद की इतनी प्रगति के बाद भी खतरनाक रूप में दिखाई दी थी। इन्हें देखकर, यहां तक कि 1952 में, स्टालिन ने वैचारिक संघर्ष तेज करने का आह्वान किया था। हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि पुराने समाज से विरासत में मिली आदत और परंपरा की ताकत, स्वामित्व की भावना इतनी आसानी से चली जाने वाली नहीं है। दास व्यवस्था के साथ पितृसत्तात्मक समाज प्रणाली, जातिगत विभाजन का आगमन प्राचीन काल से हुआ है। आज तक भी इनको जारी रखा गया है। इसी तरह, संपत्ति पर निजी स्वामित्व की भावना दास प्रथा वाले समाज में उत्पन्न हुई थी और सामंतवाद और फिर पूंजीवाद द्वारा इसे और भी मजबूत किया गया था। इसलिए हजारों साल से प्रचलित विचारों और मानसिकताओं को साफ करना इतना आसान नहीं है। लेकिन, यह बहुत ही कठिन काम पूरा किया जा सकता है अगर सही मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए विचारधारा और संस्कृति के क्षेत्र में वर्ग संघर्षों को तेज किया जाए। स्टालिन ने आगे कहा था, ''इसका कारण यह है कि वैचारिक काम का अपर्याप्त मार्गदर्शन है और इसकी सामग्री के नियंत्रण का अभाव है जिससे हम अक्सर पुस्तकों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं और वैज्ञानिक और अन्य वैचारिक संस्थाओं की गतिविधियों में गंभीर त्रुटियां और विकृतियां पाते हैं ...अगर वैचारिक काम के ऐसे क्षेत्र हैं जो किसी भी कारण से पार्टी संगठनों के दायरे से बाहर पड़ते हैं, अगर ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें पार्टी नेतृत्व और उसका प्रभाव सुस्त पड़ गया है, पार्टी द्वारा तहस-नहस कर दिये गए लेनिनवाद-विरोधी गुटों के बचे-खुचे अंश, पराये तत्व इन क्षेत्रों में पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे और वे उनका उपयोग उनकी अपनी लाइन के प्रचार के लिए, पुनरुत्थान के लिए और सभी प्रकार के गैर-मार्क्सवादी 'मतों' और 'अवधारणाओं' के प्रसार के लिए करने की कोशिश करेंगे। ... हमारी पार्टी में से कुछ संगठन आर्थिक मामलों पर ही अपना पूरा ध्यान लगा देने और ... वैचारिक मामलों को भूल जाने की ओर प्रवृत्त होंगे।'' (वही) अत: उन्होंने इससे आगाह करते हुए कहा था, ''न ही हमें यह गारण्टी हो गई है कि बाहर से, पूंजीवादी देशों से या अंदर से पार्टी पूरी तरह से जिन्हें ध्वस्त नहीं कर पायी है उन सोवियत राज्य के विरोधी शत्रुतापूर्ण गुटों के अवशेषों की ओर से पार्टी में पराये विचारों, भावों और भावनाओं की घुसपैठ नहीं की जायेगी।''(वही) हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव कमजोर होता है, तो बुर्जुआ विचारधारा प्रभाव का मजबूत हो जाएगा। गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, उन्होंने आगे चेतावनी दी थी : ''विचारधारात्मक कार्य पार्टी का मुख्य कर्तव्य है और उसके महत्व को कम करके आंकने से पार्टी और राज्य के हितों को अपूरणीय नुकसान हो सकता है।''(वही) स्टालिन ने जो चेतावनी दी थी वास्तव में हूबहू वही हुआ। सोवियत पार्टी और राज्य की एक अपूरणीय क्षति हुई थी। हमने ऊपर स्टालिन के जिस उद्धरण का जिक्र किया वह दिखाता है कि वे सोवियत राज्य के खिलाफ अन्दरूनी और बाहरी दोनों ही हमलों के खतरे से अवगत थे। साफ दिख रहा था कि निजी संपत्ति जनित मानसिकता, पुरानी नैतिकता के जोर पकड़ते जा रहे अवशेषों के प्रभाव, पुराने बुर्जुआ सुधारवादी विचारों और परम्पराओं के प्रभाव, लेनिनवाद-विरोधी गुटों की साजिश और सर्वोपरि, बुर्जुआ विचारधारा के व्याप्त होने से वे चिंतित थे। उस समय बुर्जुआ विचारधारा का प्रभाव किस हद तक व्याप्त था कि उस समय पार्टी और राज्य की होने वाली अपूरणीय क्षति और अगर वैचारिक संघर्ष तेज करने के सवाल पर समझौता किया गया, तो उससे बुर्जुआ विचारों के प्रसार में होने वाली वृद्धि से उन्होंने हमें आगाह करना पड़ा था। वे समझ गये थे कि ये समाजवाद-विरोधी अंदरूनी ताकतें बाहरी साम्राज्यवाद के साथ मिलिभगत करके समाजवाद को खतरे में डाल सकती हैं। इसलिए, उन्होंने एक और महान संघर्ष के लिए पार्टी को तैयार करने के मद्देनजर इन सभी संकटों का उल्लेख किया था। लेकिन इसके तुरंत बाद ही, उनका निधन हो गया। अत: यह संघर्ष अधूरा रह गया। यह स्पष्ट है कि इन समाजवाद-विरोधी ताकतों के प्रतिनिधि के रूप में ख्रुश्चेव ने राज्य और पार्टी का नेतृत्व हथिया लिया था जो तत्कालीन सोवियत संघ में उभर कर आई थी और जिन सब के खिलाफ स्टालिन ने संघर्ष छेड़ने का आह्वान किया था। सत्तारूढ़ होने के बाद, ख्रुश्चेव ने पूंजीवाद की बहाली की एक प्रस्तावना के रूप में संशोधनवाद की प्रक्रिया को शुरू किया था और लेनिन और स्टालिन द्वारा अपनायी गई क्रांतिकारी लाइन को छोड़ देने के विचार से, स्टालिन के खिलाफ एक निन्दा अभियान छेड़ा था तथा कॉमरेड शिवदास घोष के शब्दों में, ''संशोधनवाद की बाढ़ ला दी थी''। परिणाम के तौर पर, बुर्जुआ प्रतिक्रांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए धीरे-धीरे समाजवाद का पतन किया गया था। कॉमरेड शिवदास घोष ने ठीक ही कहा था, ''पार्टी के अंदर संशोधनवाद, उदारतावाद, बुर्जुआ प्रतिक्रांति की तमाम विकृत प्रतिक्रियावादी धारणाओं की घुसपैठ का द्वार खोल देना। सोवियत संघ के संशोधनवादी नेतृत्व ने यही किया है।''(चेकोस्लोवाकिया में सोवियत में सैन्य हस्तक्षेप और संशोधनवाद) स्टालिन को बदनाम करने के पीछे वास्तविक उद्देश्य को उजागर करते हुए उन्होंने कहा था : ''...वस्तुत: मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन सरीखे अपने पूर्ववर्तियों की तरह ही स्टालिन भी मार्क्सवाद-लेनिनवाद के बारे में एक ॲथोरिटी हैं। इसलिए स्टालिन को मिटा देने का अर्थ है उस ॲथोरिटी को ही नकार देना और इसलिए लेनिनवाद की उनकी व्याख्या को ही ठुकरा देना जोकि मार्क्सवाद-लेनिनवाद की आज के दिनों की समझ है। ... इसका मतलब हो जाएगा हर तरह के प्रतिक्रांतिकारी विचारों को मार्क्सवाद-लेनिनवाद के नाम पर चलने का न्योता दे देना और साम्यवादी आन्दोलन की सैद्धांतिक बुनियाद को धक्का पहुँचा देना।''(सीपीएसयू द्वारा स्टालिन के खिलाफ उठाए गए कदमों पर) ख्रुश्चेव और उनके सहयोगियों, चूंकि बेहद

(शेष पृष्ठ 6 पर)

6 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2018-20
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 Fortnightly

कॉ. प्रभास घोष का भाषण

(पृष्ठ 5 का शेष)

धूर्त वे थे ही, उन्हें एहसास हुआ कि जब तक स्टालिन की अॅथोरटी कमजोर नहीं होगी, तब तक वे अपने औछे मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पायेंगे क्योंकि, सोवियत लोगों के लिए, स्टालिन का नाम समाजवाद, क्रांति और मार्क्सवाद-लेनिनवाद के समानार्थी था। वे उन पर असीम विश्वास और भरोसा रखते थे और उनके मन में स्टालिन के प्रति बड़ा आदर था। हालांकि, यह अपेक्षाकृत उच्च वैचारिक स्तर के आधार पर नहीं था। इसलिए खुश्चेव जुण्डली मार्क्सवाद-लेनिनवाद और समाजवाद के नारे के साथ लोगों को भ्रमित करते हुए और स्टालिन के खिलाफ एकतरफा निंदा अभियान चलाते हुए अपनी चाल को मूर्त रूप दे पाई। अगर एक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों व कार्यकर्ताओं के साथ ही जनसाधारण का भी वैचारिक स्तर बहुत नीचा हो, तो यह कितने बड़े खतरे का सबब हो सकता है यह सोवियत संघ का उदाहरण देते हुए कॉमरेड शिवदास घोष ने इंगित किया था। उन्होंने कहा था : ''संस्कृति एवं ज्ञान का स्तर निम्न रहने से पूरी पार्टी व सम्पूर्ण मजदूर वर्ग गुमराह होकर, गलत रास्ते भटक कर समाजवाद का नारा जपते हुए तथा मार्क्सवाद-लेनिनवाद का झण्डा फहराते हुए ही सुधारवाद व संशोधनवाद के रास्ते पूंजीवाद को पूरी तरह वापस ला सकता है।''(चीन की क्रांति सांस्कृतिक) इस संबंध में, मैं आपको 1948 में जब विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन पूर्ण गौरव पर था, तब कॉमरेड शिवदास घोष ने जो चेतावनी दी थी उसे याद दिलाना चाहूंगा। कॉमरेड शिवदास घोष ने चेतावनी दी थी, '' विभिन्न देशों के कम्युनिस्टों ने अभी तक अधिकांशत: सैद्धांतिक मामलों के साथ सांगठनिक कामों के समन्वय को कोई तवज्जो दिए बिना ही संगठन के रोजमर्रे के कार्यों पर ही एकतरफा जोर दिया। ... इसका अंतत: नतीजा यह हुआ कि विचारों की अंतर्क्रिया के माध्यम से क्रांतिकारी कम्युनिस्ट नेतृत्व के उभरने-बनने की द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया के सम्बन्ध में ऐतिहासिक तजुर्बों की कसौटी पर खरे उतरे मार्क्सवादी विज्ञान को ही नकार दिया गया है।'' (कम्युनिस्ट खेमे की आत्मालोचना) कुछ दिन के बाद, कॉमरेड शिवदास घोष ने एक और कमी को इंगित करते हुए कहा था कि, ''... लेनिनोत्तर काल में यह देखा गया है कि जनजीवन और वर्ग-संघर्ष की नई-नई समस्याओं की अधिकता और प्राकृतिक विज्ञान में हुई हैरतअंगेज प्रगति के चलते मार्क्सवाद-लेनिनवाद का जो दार्शनिक विकास कराना चाहिए था, वह नहीं कराया गया।''(सीपीएसयू द्वारा स्टालिन के खिलाफ उठाये गए कदम पर) सीपीएसयू की 19वीं पार्टी कांग्रेस की उनकी रिपोर्ट में स्टालिन ने भी इस कमी को स्वीकार किया था। लेनिन की मृत्यु के बाद, पार्टी के भीतर उत्पन्न गहरे संकट से निपटने के लिए स्टालिन ने समाजवादी पुनर्निर्माण की तेज प्रगति सुनिश्चित करने के कार्य का निर्वहन करते हुए, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले प्रतिक्रांतिकारी उभार को विफल करते हुए और दूसरे विश्व युद्ध में फासीवादी धुरी के खिलाफ जीवन-मरण का संघर्ष चलाते हुए लगभग पूरा समय लगाया था। इसलिए, वे मार्क्सवाद-लेनिनवाद के दार्शनिक विकास में योगदान के उस कार्य पर उतना ध्यान नहीं दे सके थे। हालांकि, उसकी मृत्यु से ठीक पहले, उन्होंने इस कार्य को हाथ में लिया और समाजवादी अर्थव्यवस्था और भाषा विज्ञान की समस्या पर दो अमूल्य पुस्तकें लिखी। लेकिन अचानक मृत्यु हो जाने के कारण, अन्य क्षेत्रों में इसी तरह का योगदान नहीं कर पाये।

कॉमरेड शिवदास घोष ने किया था कम्युनिस्ट चरित्र के नए उच्च स्तर को परिभाषित

कॉमरेड शिवदास घोष ने दो और भी अधिक महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान खींचा। सबसे पहले, उन्होंने कहा था, ''रूसी समाज में तथा क्रांति के इतने दिनों बाद भी चीनी समाज में देश की जनसंख्या के अनुपात में मार्क्सवादी-लेनिनवादी पद्धति से सोचने-विचारने के अभ्यस्त लोगों की संख्या नितांत नगण्य है। जो मोटे तौर पर मार्क्सवाद-लेनिनवाद कुछ-कुछ समझते भी हैं इस तरह के लोगों में भी मार्क्सवाद-लेनिनवाद का केवल सतही असर है। फिर वे सब लोग जो मार्क्सवादी-लेनिनवादी पद्धति से सोचते-विचारते हैं और कार्य करते हैं, अर्थात पार्टी में जो-जो हैं–उनमें भी बुर्जुआ विचारधारा की भ्रांतियाँ एवं आधुनिक संशोधनवाद का प्रभाव दिखाई दे रहा है।'' (चीन का क्रांति सांस्कृतिक) फिर, उन्होंने आगे कहा था : ''चीनी क्रांति एक साम्राज्यवाद-विरोधी, सामंतवाद-विरोधी, लोगों की जनवादी क्रांति थी–मजदूर वर्ग के नेतृत्व के तहत लोगों की जनवादी क्रांति थी। राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग इस क्रांति का एक सहयोगी था। रूस में बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति के एक निश्चित चरण तक, पूंजीपति वर्ग ने वहाँ कुछ कदम क्रांति के मार्ग पर उठाये थे और कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन में रहे थे। इसके बाद, सत्ता में बैठा पूंजीपति वर्ग इससे पहले कि बुर्जुआ वर्ग शासन को स्थिरता प्रदान कर सके, रूस में सर्वहारा वर्ग ने तेजी से पूंजीपति को राज्यसत्ता से उखाड़ फेंका और समाजवादी क्रांति सफल की, और इसके बाद, यह मजदूर वर्ग नेतृत्व के हाथ में है कि वह बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति के अधूरे कार्यों को पूरा करे। इस वजह से उस समय वहाँ व्यक्तिवाद की अपेक्षाकृत प्रगतिशील भूमिका थी।''('Science of Marxism is the Scientific Dialectical Methodology' अर्थात् मार्क्सवाद का विज्ञान वैज्ञानिक द्वंद्वात्मक कार्यप्रणाली है) उन्होंने इस तरह से दिखाया था कि क्रांति के दौरान और यहां तक कि इसके बाद भी कुछ समय तक व्यक्तिवाद की एक सापेक्षत: प्रगतिशील भूमिका थी। परंतु, बुर्जुआ व्यक्तिवाद का प्रभाव उसके बाद भी बना रहा, जिसे देख कर उन्होंने कहा था, ''... समाजवादी समाजव्यवस्था में आर्थिक तथा राजनैतिक रूप से तुलनात्मक रूप में स्थायित्व हासिल होने के साथ-साथ व्यक्ति स्वाधीनता, व्यक्ति मुक्ति व व्यक्ति स्वातंत्र्यबोध सुविधा के साधन में पर्यवसित होने का रुझान देखा जा रहा है, जिसको मैंने पहले ही 'समाजवादी व्यक्तिवाद' की संज्ञा दी है जिसका अर्थ है समाजवादी व्यवस्था में एक नये किस्म का व्यक्तिगत सुविधावाद।'' (चीन की सांस्कृतिक क्रान्ति) फिर उन्होंने कहा : '' 'जो सामाजिक स्वार्थ के सामने व्यक्तिगत स्वार्थ को बिना शर्त मातहत कर सकते हैं, हर वक्त पार्टी व क्रांति के स्वार्थ को ऊपर मानते हैं एवं उसके सामने व्यक्तिगत स्वार्थ को बिना शर्त सरेण्डर कर सकते हैं वही सच्चे कम्युनिस्ट हैं'–आज तक कम्युनिस्ट मूल्यबोध का सर्वोच्च स्तर यही था। कालिनिन की किताब *'कम्युनिस्ट ऐडूकेशन'* में इसे ही सही कम्युनिस्ट चेतना का उच्चतर स्तर कहा गया है। ... लेकिन आज की नई परिस्थिति में यह ऊँचे दर्जे के सच्चे कम्युनिस्ट का स्तर नहीं हो सकता। ... समाजवादी व्यवस्था में व्यक्ति का मुक्ति-संग्राम एक नए जटिल चरण में आ पहुंचा है और एक नया रूप धारण कर लिया है, जहां इस समस्या के समाधान के लिए अडिग निष्ठा और सतत जागरूकता के जरिये व्यक्तिगत स्वार्थ को सामाजिक स्वार्थ के साथ विलय कर देने के लिए और भी जोरदार कठोर संघर्ष को चलाना होगा। अतएव न्याय-नीति व मूल्यबोध का यह एक नया स्तर है जो पुराने बुर्जुआ मानवतावादी मूल्यबोध जिन्हें कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन में कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए अब तक इस्तेमाल किया जाता रहा, उससे सम्पूर्णत: भिन्न है।''(वही) मैं आपको कॉमरेड शिवदास घोष द्वारा दी गई एक और चेतावनी याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था : ''व्यक्ति-स्वार्थ के साथ सामाजिक स्वार्थ का जो द्वंद्व है उसका स्वरूप विरोधात्मक है।...अत: व्यक्तिगत स्वार्थ तथा सामाजिक स्वार्थ के बीच विरोधात्मक द्वंद्व के प्रतिफलन के तौर पर राजसत्ता जब तक बरकरार रहेगी तब तक समाजवादी व्यवस्था में भी व्यक्ति को सामाजिक स्वार्थ के सामने 'सब्मिट' (आत्मसमर्पण) करना ही पड़ेगा तथा तब तक समाजवादी राजसत्ता के दमनात्मक चरित्र के खिलाफ व्यक्ति मानस में विद्रोह करने की प्रवृत्ति बार-बार दिखाई देती रहेगी। इसके परिणास्वरूप सामाजिक लक्ष्य बार-बार मार खाता रहेगा। ...उसमें सामाजिक उदासीनता की मानसिकता बढ़ती जाएगी। फलस्वरूप, कम्युनिस्ट विचारधारा की जो शक्ति है, निष्ठा-लगन का जो बल है वह घटता जाएगा। अथवा एक और चीज होगी–उदारीकरण। अर्थात् लगातार मांग उठेगी कि व्यक्ति के अधिकारों को और बढ़ाया जाए। और इस तरह चलते रहने से यह फिर संशोधनवाद को जन्म देगा तथा पूंजीवाद को ही वापस लाने में मदद करेगा।'' (वही)

जिनसे संशोधनवाद सोवियत संघ में अपना मनहूस सिर उठा पाया उन कारणों को दर्शाते हुए, उन्होंने कहा था : ''जैसे वहाँ सामूहिक खेती की प्रणाली है, पण्य उत्पादन और परिचालन (commodity circulation) की प्रणाली है, निजी सम्पत्ति जैसे घर-द्वार, रुपये-पैसे, बैंकों में रुपये जमा करना आदि है, मूल्य का नियम (सूत्र अंसनम) लागू है। इन सारी चीजों के जरिये यह प्रतिबिम्बित होता है कि वहाँ निजी सम्पत्ति का बीज नष्ट नहीं हुआ है और यह जब तक रहता है तब तक अर्थव्यवस्था में समाज के अंदर पूँजीवादी रुझान बना रहता है। ... लेकिन, शुरूआती समय में उसमें जितनी ताकत होती है, समाजवाद सफलता की ओर जितना अग्रसर होता जाता है, आर्थिक मामले में पूंजीवाद उतना ही परास्त होकर हमला करने की, प्रतिरोध करने की, प्रतिक्रांति लाने की अपनी ताकत खोता जाता है। हालांकि ऊपरी ढाँचे अर्थात् वैचारिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में वर्ग संघर्ष और तीव्र व सूक्ष्म रूप अख्तियार कर लेता है। ... इसे रोकने के लिए एक ओर पार्टी के अंदर निरंतर सांस्कृतिक क्रांति और वैचारिक संघर्ष चलाकर वैचारिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में चेतना का उन्नत स्तर बरकरार रखने की, दूसरी ओर सिर्फ आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि मानव जीवन को केन्द्र कर बदले हुए परिवेश में उभर कर आ रही नयी-नयी समस्याओं का मुकाबला करने के लिए मार्क्सवाद को लगातार समृद्ध करने की जरूरत थी।'' (चेकोस्लोवाकिया में सोवियत सैन्य हस्तक्षेप)

पहले से ही यह विचार कि मुट्ठीभर मालिक लोग विशाल धन के अम्बार लगा लेंगे और बहुसंख्यक आबादी दमित और वंचित बनी रहेगी, लोगों के दिमाग में शोषणकारी दास-समाज, सामंतवाद और पूंजीवाद के दौरान पैदा किया गया था। इसी तरह, एक और बात समझायी गई थी कि केवल कुछ प्रतिभाशाली और बुद्धिमान लोग ही ज्ञान के हकदार होंगे और बहुसंख्यक जनता शारीरिक श्रम प्रदान करेगी और ज्ञानार्जन नहीं करेंगे। हर किसी में प्रतिभा नहीं है। मार्क्स-एंगेल्स-लेनिन-स्टालिन-शिवदास घोष को न केवल आर्थिक मुक्ति के लिए लड़ना पड़ा था, बल्कि उन्होंने सभी के लिए ज्ञान हासिल करने के अवसर खुलवाने के लिए भी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन समस्या ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और सर्वहाराओं को तकलीफें उठाने और कठिनाइयां झेलने, किसी भी कठोर काम और यहां तक कि क्रांति करने के लिए मृत्यु को गले लगाने के लिए तो तैयार किया जाता है, लेकिन अगर अंधविश्वास के चलते नहीं, तो सैकड़ों सालों से निर्मित एक परंपरागत विरासत में पायी मानसिकता की वजह से वे ज्ञान को विकसित करने के लिए उत्सुक नहीं हैं। उनमें उदासीनता की भावना काम करती है। यही वजह है कि स्टालिन ने कहा था कि ''सैद्धांतिक काम पार्टी का एक मुख्य कर्तव्य है और उसके महत्व को कम करके आंकने से पार्टी और राज्य के हितों को अपूरणीय क्षति हो सकती है।''(सीपीएसयू की 19वीं कांग्रेस की रिपोर्ट) हालांकि पार्टी कार्यकर्ता और जनसाधारण उनका बहुत आदर-सम्मान करते थे, लेकिन उनकी इस अपील का उन्होंने प्रत्युत्तर नहीं दिया। उस के कारण कितना भारी नुकसान हुआ है? इससे हमें उचित सबक लेने की जरूरत है।

महान माओ त्से-तुंग ने चीन में प्रतिक्रांति को विफल करने के लिए सांस्कृतिक क्रांति के दौरान किये गए अपने आह्वान में कहा था कि ''हालांकि, बुर्जुआ को खत्म कर दिया गया है, वह अभी भी लोगों को पथभ्रष्ट करने, उनके दिमाग पर अपनी पकड़ बनाने के लिए शोषक वर्गों के पुराने विचारों, संस्कृति, रीति-रिवाजों और आदतों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और वापस आने का भरसक प्रयास कर रहा है। सर्वहारा वर्ग को इसके एकदम विपरीत करना चाहिए : इसे वैचारिक क्षेत्र में बुर्जुआ वर्ग की हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और पूरे समाज के मानसिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए सर्वहारा वर्ग के नए विचारों, संस्कृति, रीति-रिवाजों और आदतों का इस्तेमाल करना चाहिए। वर्तमान में, हमारा उद्देश्य है अथोरटी रखने वाले उन व्यक्तियों के खिलाफ संघर्ष करना और उनको उखाड़ फेंकना जो पूंजीवादी रास्ता ले रहे हैं।'' (महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के संबंध में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी का निर्णय)

इतने लंबे समय तक, मैंने मार्क्स-एंगेल्स-लेनिन-स्टालिन-माओ त्से-तुंग-शिवदास घोष को उद्धृत करके

(शेष पृष्ठ 7 पर)

कॉ. प्रभास घोष का भाषण

(पृष्ठ 6 का शेष)

यह दिखाने की कोशिश की है कि उन सब ने एक बात सिखाई थी कि समाजवाद की स्थापना और समाजवाद की प्रगति के बाद भी, बुर्जुआ कारक जो हैंगओवर के रूप में बरकरार रहते हैं, प्रतिक्रान्ति को रोकने के लिए उनको समाप्त करना होगा भीषण वैचारिक संघर्ष चलाते हुए लोगों को क्रांतिकारी विचारधारा से लैस करने के द्वारा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि समाजवाद में चूंकि बुर्जुआ लाक्षणिकताएं और कारक अस्तित्व में हैं, इसलिए प्रतिक्रान्ति होना अवश्यम्भावी है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिक्रान्ति को रोकने के लिए पार्टी और लोग अपने सैद्धांतिक स्तर को ऊपर उठाने के रास्ते ठीक से संघर्ष कर रहे हैं या नहीं। अर्थव्यवस्था में बुर्जुआ तत्वों और लाक्षणिकताओं को लगभग नष्ट करके समाजवादी आर्थिक संरचना को मजबूत कर रहे हैं या नहीं और साथ ही साथ अधिरचना में बुर्जुआ विचारों, भावना-धारणाओं, निजी संपत्ति जनित मानसिक ग्रंथि, संस्कृति, आदतों की शक्तियों और पुराने समाज से विरासत में मिली परंपराओं के तमाम नामोनिशान खत्म करने के लिए सही ट्रैक पर गहन वैचारिक संघर्ष चला रह हैं या नहीं। अन्यथा, अधिरचना से प्रतिक्रान्तिकारी हमला सामाजिक-आर्थिक आधार को भी नष्ट कर देता है। इसके बारे में हमें मार्क्सवादी ॲथोरटियों की उपरोक्त शिक्षाओं से उचित सबक लेने हैं।

दुनिया के लिए विनाशकारी रहा समाजवाद का ढह जाना

रोमां रोलां द्वारा बहुत अरसे पहले दिखाया गया था कि सोवियत समाजवाद अगर उलटफेर से रूबरू हुआ, तो मानव जाति का कितना गम्भीर अहित होगा। उन्होंने कहा था, ''अगर यह (सोवियत संघ) कुचल दिया गया तो यह केवल दुनिया का सर्वहारा वर्ग ही अकेला गुलाम नहीं बन जाएगा बल्कि सामाजिक या व्यक्तिगत हर तरह की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी... दुनिया कई सदियों पीछे धकेल दी जाएगी।''(आई विल नोट रेस्ट) हूबहू वैसा ही हुआ है। जब तक शक्तिशाली समाजवादी खेमा अस्तित्व में रहा, तब तक न केवल विभिन्न देशों के क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ-साथ साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन मजबूत हुए, बल्कि युद्ध-विरोधी शांति आन्दोलनों के साथ-साथ प्रगतिशील जनवादी आन्दोलन भी मजबूत हुए। मूल्यबोधों का सृजन हुआ। इन सब कुछ को काफी नुकसान पहुंचा है। साम्राज्यवादी-पूंजीवादियों द्वारा भड़काये गये अंधराष्ट्रवाद-जातिवादी उन्माद-साम्प्रदायिक विद्वेष-नस्ली नफरत, धार्मिक कट्टरतावाद, धार्मिक आतंकवाद और भयावह हत्याकाण्डों के साथ-साथ जनवादी चेतना की कमी और मूल्यबोधों के अभाव ने सभी देशों में गंभीर संकट पैदा कर दिया है। अगर समाजवादी खेमा बरकरार होता तो, अमेरिकी साम्राज्यवाद न तो इराक, लीबिया और अफगानिस्तान को नष्ट करने में कभी सक्षम हुआ होता और न ही सीरिया पर हमला कर पाया होता। उदारहण के लिए 1956 में अमेरिका की शह पाकर इंग्लैंड और फ्रांस ने स्वेज नहर पर अपना वर्चस्व कायम करने को लेकर मिस्र पर हमला बोल दिया था। लेकिन जिस वक्त सोवियत यूनियन ने अल्टीमेटम दिया, तो उन्हें उसी समय पीछे हटना पड़ा था।

इन सबके मद्देनजर यह वास्तव में बहुत दुखदायी है कि वह समाजवाद प्रतिक्रांतिकारी जुण्डली की वजह से ढह गया है। पर उसके लिए निराश होने का कोई कारण नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि धार्मिक आन्दोलनों के साथ-साथ बुर्जुआ जनवादी क्रांति ने केवल एक तरह की दमनकारी व्यवस्था की जगह दूसरी तरह की दमनकारी व्यवस्था कायम की थी। फिर भी उन्हें अन्तिम विजय हासिल करने में सैकड़ों साल लगे थे। उन सैकड़ों सालों की तुलना में 70 साल का अरसा सदा-सदा के लिए उत्पीड़न का खात्मा करने वाले एक आन्दोलन की जीत के लिए बहुत थोड़ा अरसा है। इसलिए हमें उपयुक्त सबक लेना चाहिए कि समाजवाद ढहने के पीछे क्या कारण रहे और आने वाले दिनों में सर्वहारा क्रान्ति कैसे पूरी की जाए। क्रांति में 1871, पेरिस कम्यून की अवधि केवल तीन महीने ही रही थी। इसके बाद, पूंजीपति वर्ग ने इसे ध्वस्त कर दिया था। मार्क्स ने इस उलटफेर से आवश्यक शिक्षा ली थी और कहा था कि जब तक बुर्जुआ राज्य मशीन चकनाचूर नहीं कर दी जाती, तब तक मजदूर वर्ग की क्रांति विजयी नहीं होगी। लेनिन ने इस सीख को लागू किया। इसी तरह, आने वाले दिनों में, सोवियत समाजवाद की हार से सीख लेकर कम्युनिस्ट लोग प्रतिक्रांतिकारी हमले से समाजवाद की रक्षा करेंगे और इसे आगे ले जाएगें। वे आइन्दा समाजवाद को किसी भी खतरे में नहीं पड़ने देंगे। इसलिए हमारे लिए काम क्या है? हमारे सामने दो विकल्प हैं, क्या हमें साम्राज्यवाद-पूंजीवाद को सदा बने रहने देना चाहिए और शोषण-उत्पीड़न को चलते रहने देना चाहिए, बेतहाशा बढ़ती बेरोजगारी, छंटनी, भुखमरी, आत्महत्याओं, देह व्यापार,, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार, छोटी बच्चियों और वृद्ध महिलाओं से बलात्कार, मानवीय गुणों और इन्सानियत के खात्मे, मूल्यबोधों के उन्मूलन, जमीर को मरते देखकर क्या हम मूक दर्शक बने रहें या इन सब खतरों और पथ-भ्रष्टता से निजात पाने के लिए भरसक कोशिश करनी चाहिए। इस वांछित मुक्ति का रोडमैप क्या है? यह रोडमैप महान नवंबर क्रांति ने तैयार किया है।

हमें बचाना है मानव सभ्यता कोबर्बादी के कगार से

आज, मानव सभ्यता बर्बादी के कगार पर है। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था एक सड़ी-गली बदबूदार लाश में बदल गई है। समाज इतना अमानवीय हो गया है कि सम्पत्ति के लिए बच्चों द्वारा बूढ़े माता-पिता गला घोंट कर मार दिये जाते हैं। पति अपनी पत्नी की हत्या कर रहा है या उसे बेच रहा है। यह है पूंजीवाद की देन। कोई मानवीय भावना नहीं, काई मानवीय सार नहीं, कोई मूल्य बोध या संस्कृति नहीं। बुर्जुआ पार्टियां सत्ता और धन-दौलत के चक्कर में हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों, कॉर्पोरेट घरानों और एकाधिकारी पूँजीपतियों की सेवा करना। धन्नासेठों के समर्थन से सत्तारूढ़ होने के बाद वे भी अपने वारे नारे कर रही हैं। अकूत काले धन के अंबार लगा रही हैं। महज कुछ ही दिन पहले, पनामा पेपर्स घेटाला सामने आया था। हाल ही में, पैराडाइज पेपर्स घोटाला भी सामने आया है। दोनों ही काले धन से जुड़े बड़े घोटाले हैं। खबर है कि लगभग 417 राजनेता, मंत्री और उद्योगपति घोटालों में संलिप्त हैं। इस सूची में कई दूसरे देशों के कई नेता, मंत्री-उद्योगपतियों के नाम भी इस सूची में हैं। स्वीस बैंक ने भारत के 1000 काले धन धारकों के नाम दिये हैं। सरकार ने उनके खिलाफ क्या कदम उठाये हैं? शासक दल के नेता और मंत्री झूठे वायदों और थोथे दावों की झड़ी लगाकर केवल गाल बजा रहे हैं। जितना ज्यादा वे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, भ्रष्टाचार, उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। वे खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। क्या हम इसे ऐसी ही चलने दें? तब, भविष्य क्या रह जाएगा? इसका इलाज केवल नवम्बर क्रांति के रास्ते पर चलते हुए समाजवाद कायम करना ही है। यह देखकर दिल को दिलासा मिलती है कि शोषित-उत्पीड़ित लोग अक्सर अपना सिर उठा रहे हैं और स्वत:स्फूर्त प्रतिवादों में उनका आक्रोश फूट पड़ रहा है। अमेरिका के 'वाल स्ट्रीट पर कब्जा करो' जैसे आन्दोलन बार-बार उभरेगें। इस आन्दोलन ने अमेरिकी साम्राज्यवादी हुकूमत को हिला कर रख दिया था। जायज मांगों को लेकर एक पर एक हो रही मजदूरों की हड़तालों ने पूरे यूरोप, खासकर ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस को अपनी चपेट में ले लिया है। हमारे देश में भी, मजदूर, किसान, छात्र-नौजवान, महिलाएं और मेहनतकश जनता के अन्य सभी तबके लाठी-गोली का बहादुरी से सामना करते हुए संघर्षों को गठित कर रहे हैं। आन्दोलन की ज्वाला प्रज्वलित है, वे बदलाव चाहते हैं, शोषण से मुक्ति और छुटकारा पाना चाहते हैं। परंतु वे नहीं जानते कि यह बदलाव कैसे आयेगा या ये मुक्ति कैसे मिलेगी। केवल मार्क्सवाद-लेनिनवाद- शिवदास घोष चिंतनधारा ही रास्ता दिखा सकती है। केवल नवम्बर क्रांति ही प्रकाश स्तम्भ की तरह राह रोशन कर सकती है। इतिहास ने यह काम हमें सौंपा है। हमनें इस काम को पूरा करने के लिए चौतरफा पहल कदमी की है। महज एक हॉल मीटिंग करके रस्म अदायगी के तरीके से इस महान नवंबर को नहीं मनाया है। हमने देशभर में नवम्बर क्रान्ति के संदेश को फैलाने के लिए वर्षव्यापी अभियान चलाया। यह एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अभियान से लोग अत्यन्त प्रेरित हुए हैं। उन्होंने हमें समर्थन दिया है और हमारे संघर्ष कोष में दिल खोल कर दान दिया है। इससे हमं खुद भी प्रेरित हुए हैं।

इसलिए मैं यह बात दोहराना चाहता हूँ कि साम्राज्यवाद-पूंजीवाद मृत्यु-शैया पर है। केवल सचेत मजदूर वर्ग ही इस चिता में आग लगा सकता है अगर वह मार्क्सवाद लेनिनवाद-शिवदास घोष चिंतन से प्रभावित हो और खुद को संगठित कर ले; अगर वे पहले जनसंघर्ष कमेटियां गठित कर लें और बाद में उच्च नीति-नैतिकता के आधार पर क्रांतिकारी कमेटियां और स्वयंसेवक दस्ते बना लें। सबसे पहले, उन्हें अन्य सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टियां के साथ मिलकर साझे न्यूनतम कार्यक्रम पर आधारित संयुक्त जनवादी आन्दोलन विकसित करना होगा, इस प्रक्रिया में इन पार्टियों को जनता से अलग-थलग करना होगा, जनता पर क्रांतिकारी नेतृत्व कायम करना होगा और इस तरह आगे बढ़ना होगा। हमें भारत में यह जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारा काम है हमें वर्ग संघर्ष और जन आन्दोलन गठित करने होंगे तथा वर्ग संगठन बनाने होंगे। लेनिन ने सिखाया था कि जब तक बुर्जुआ संसदीय प्रणाली से लोगों का सकारात्मक मोहभंग नहीं हो जाता, तब तक क्रांतिकारियों को भी सदन में जन आन्दोलन की आवाज को गुंजाने और साथ ही साथ जनजीवन की ज्वलंत समस्याओं पर गैर-संसदीय आन्दोलन गठित करने के निश्चित क्रांतिकारी उद्देश्य के साथ चुनाव में भाग लेने और सीट जीतने की कोशिश करने और वर्ग संघर्ष को तेज करने की जरूरत है। चुनाव से क्रान्ति नहीं आयेगी। यह लेनिन की सीख है। परंतु सीपीआई (एम) और सीपीआई उस दिशा में आगे नहीं बढ़ रही हैं। यही वजह है कि लेनिन की शिक्षा के आधार पर, कॉमरेड शिवदास घोष ने 1967 में पश्चिम बंगाल में पहली संयुक्त मोर्चा सरकार के समय कहा था कि हम, वामपंथियों को उस तरह सरकार नहीं चलानी चाहिए जिस तरह से बुर्जुआ वर्ग की पार्टियां चलाती हैं, बल्कि वर्ग संघर्ष और जन आन्दोलन को मजबूत करने के लिए सरकार चलानी चाहिए। लेनिन के समय में, बुर्जुआ ढांचे में वामपंथियों के लिए सरकार बनाने का कोई भी अवसर नहीं आया था। इसलिए लेनिन ने इस पर कोई दिशानिर्देश प्रदान नहीं किया था। लेनिन की शिक्षाओं को विकसित करते हुए, कॉमरेड शिवदास घोष ने कहा कि भले ही वामपंथियों ने सरकार बनाई हो, उस सरकार को भी वर्ग संघर्ष को तेज करने के उसी उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए। इस सवाल पर, हमारे और सीपीआई(एम) के बीच गहरा मतभेद था। बुर्जुआ दृष्टिकोण और रुख-रवैये के साथ 34 वर्षों के सीपीआई (एम) के शासन के बाद, आप भली-भांति देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल, जो एक समय वाम-जनवादी आंदोलन और वर्ग संघर्ष के गढ़ के रूप में जाना जाता था, हर मामले में कैसे पतित हो गया है। इस सभा में मौजूद सीपीआई(एम) के नेताओं और कार्यकर्ताओं यह समझना चाहिए।

हम दृढ़ता से बुलंद करेंगे नवंबर क्रांति का बैनर

हम लोगों की ज्वलंत मांगों पर जनवादी आंदोलन गठित करते जा रहे हैं। हम और भी बड़े पैमाने पर निर्माण होगा गरीब मजदूरों और किसानों के संघर्ष गठित करेंगे और उसके साथ ही स्पष्ट क्रांतिकारी उद्देश्य से चुनाव भी लड़ेंगे। अगर कोई दूसरी सामाजिक जनवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ना चाहती है, तो हम उनके साथ संयुक्त आंदोलन गठित करेंगे। सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के दृष्टिकोण और क्रांतिकारी भाईचारे से निर्देशित, हम बांग्लादेश के क्रांतिकारी आंदोलन की मदद और समर्थन करेंगे। इसी तरह विभिन्न देशों में साम्यवादी आन्दोलन विकसित करने के लिए हर पहलकदमियों की हम मदद करेंगे। मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि तमाम रास्ते नवम्बर क्रांति की ओर जाते हैं। नवम्बर क्रांति के इस संदेश को आग ले जाएं।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद शिवदास घोष चिंतन जिंदाबाद!
सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद जिंदाबाद!
इंकलाब जिंदाबाद!
एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) जिंदाबाद!
बांग्लादेश समाजतांत्रिक दल (मार्क्सवादी) जिंदाबाद!
मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ त्से-तुंग, शिवदास घोष लाल सलाम! ●●●

8 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2018-20
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 of every month, Fortnightly, Date of Publication : January 20, 2018

सर्वहारा दृष्टिकोण

22 जनवरी से 5 फरवरी, 2018

एफडीआई का उदारीकरण बीजेपी सरकार का एक निर्लज्ज एकाधिकारी पूंजीपति-परस्त कदम

इसे रोके जाने की है जरूरत –एसयूसीआई (सी)

एसयूसीआई सी के महासचिव कामरेड प्रभास घोष ने 11 जनवरी 2018 को निम्नलिखित बयान जारी किया :

अपनी संकल्पित जनविरोधी एकाधिकारी पूंजीपति-परस्त नीति के निर्देशनानुसार कोर सेक्टरों के लगातार निजीकरण के प्रयास के खिलाफ उभरते जनमत की अवहेलना करते हुए बीजेपी सरकार ने अब सिंगल ब्रांड रिटेल में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की घोषणा कर दी है। जमीन जायदाद का धंधा करने वाली फर्मों में 100% एफडीआई की इजाजत देकर जमीन-जायदाद और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी एफडीआई नीति के संदर्भ में 'मेडिकल डिवाइसेस' की परिभाषा को संशोधित करके ज्यादा मात्रा में विदेशी पूंजी की घुसपैठ के द्वार खोल दिए हैं। इस बात की पूरी-पूरी संभावना है कि कुछ ही समय में मल्टी ब्रांड रिटेल में भी एफडीआई के हमले का रास्ता साफ कर दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी संख्या में गरीब लोगों को आजीविका मुहैया कराने वाली घरेलू छोटी-छोटी खुदरा दुकानों के अंततः बंद हो जाने और खुदरा क्षेत्र में भारी रोजगार हानि के रूप में इसका भयंकर दुष्परिणाम सामने आएगा। इसके अलावा, एक बार जब देशी-विदेशी एकाधिकारी पूंजी अपनी जड़ें जमा लेगी तब 'एकाधिकारी मूल्य नीति' पहले से ही बढ़ी महंगाई में और भी उछाल ला देगी।

यह भी नजर में आ रहा है कि भारतीय एकाधिकारी पूंजीपति जो पहले ही वित्तीय गुटतंत्र के रूप में उभर कर आ चुके हैं और एफडीआई की शक्ल में विदेशों में वित्तीय पूंजी के निर्यात के जरिए साम्राज्यवादी चरित्र हासिल कर चुके हैं, मंदी की मार से ग्रसित भूमंडलीय बाजार में कड़े मुकाबले का सामना कर रहे हैं। इसलिए अपना खुद का बाजार साम्राज्यवादी ताकतों, विशेषकर अमेरिकी साम्राज्यवाद के लिए खोल रहे हैं ताकि बदले में विभिन्न विदेशी बाजारों में घुसपैठ करने के लिए कुछ रियायतें-छूट, तरजीह और सहूलियतें हासिल की जा सकें। यही मजबूरी है जो रक्षा क्षेत्र सहित देश की अर्थव्यवस्था को एफडीआई की खातिर उत्तरोत्तर खोल देने के लिए पूंजीपति वर्ग के स्वार्थ की रक्षक बीजेपी सरकार को प्रेरित कर रही है। यह भी गहन चिंता के साथ नोट किया जा रहा है कि जहां स्थिति संसद के बाहर और भीतर दोनों जगह जोरदार प्रतिवादी आंदोलन छेड़ने की मांग कर रही है, वही विपक्ष, विशेषकर जो अपने को मार्क्सवादी-वामपंथी कहते हैं, वे इस मामले में सिर्फ औपचारिक बयानबाजी करने के सिवा और कोई ठोस पहलकदमी नहीं ले रहे हैं। यह भी स्मरण रहे कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में एफडीआई के उदारीकरण की नीति लागू की थी और जब पश्चिम बंगाल में सीपीआई(एम) सत्ता में थी, तब इसने औद्योगिकीकरण और विकास के नाम पर एफडीआई-परस्त नीतियां लागू की थी। वे सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए विरोध का दिखावा कर रहे हैं। हम देशवासियों का आह्वान करते हैं कि वे आगे आएं और सही नेतृत्व के तहत पूरी ताकत के साथ जोरदार संगठित सचेत जन आंदोलन गठित करने का बीड़ा उठायें ताकि पूंजीवादी सरकार की ऐसी विनाशकारी नीतियों को रोका जा सके और करोड़ों मेहनतकशों की रोजी-रोटी बचायी जा सके।

स्कीम वर्करों की देशव्यापी हड़ताल पर संयुक्त जुलूस निकाला

दिल्ली : 17 जनवरी को अखिल भारतीय हड़ताल के दिन एआईयूटीयूसी, सीटू, एटक, एचएमएस, एआईसीसीटीयू से संबद्ध स्कीम वर्करों की यूनियनों के हजारों कर्मियों ने मंडी हाउस से संसद मार्ग तक एक संयुक्त जुलूस निकाला। वहां आयोजित विरोध सभा को एआईयूटीयूसी दिल्ली राज्य सचिव और दिल्ली आशा वर्कर्स एसोसियेशन (डीएडब्ल्यूए) के अध्यक्ष कॉ. मैनेजर चौरसिया व अन्य लोगों ने संबोधित किया था।

भिवानी (हरियाणा) 17 जनवरी को परियोजना वर्करों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तत्वावधान में जिला भिवानी में आशा कार्यकर्ता यूनियन, मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका यूनियन सम्बन्धित एआईयूटीयूसी और आशा वर्कर्स यूनियन, मिड डे मील वर्कर्स यूनियन, आंगनबाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स यूनियन सम्बन्धित सीटू, दोनों ट्रेड यूनियनों की तरफ से सैकड़ों की संख्या में स्कीम कर्मी स्थानीय नेहरू पार्क में एकत्रित हुई। वहां हुई संयुक्त सभा के अध्यक्षमण्डल में एआईयूटीयूसी की तरफ से पूजा और सीटू की तरफ से किताब कौर रही। सभा को एआईयूटीयूसी की ओर से कॉ. राजकुमार बासिया और सीटू की तरफ से कॉ. ओमप्रकाश ने सम्बोधित किया। सभा का संचालन एआईयूटीयूसी की ओर से कॉ. धर्मवीर सिंह और सीटू की तरफ से कॉ. धर्मवीर कुंगड़ ने किया।

सभा को सम्बोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन के अनुमोदन के अनुसार सरकार परियोजना वर्करों को मजदूर मानकर न्यूनतम वेतन तक नहीं दे रही है। सरकार इन परियोजनाओं के बजट में कटौती करके इनका निजीकरण कर रही है। इससे परियोजना वर्करों में भारी असंतोष है। इसलिए परियोजना वर्करों ने अपनी मांगों के समर्थन में राष्ट्रव्यापी हड़ताल करके सभी वर्करों को पक्का करने, न्यूनतम वेतन व सेवानिवृत्ति लाभ लागू करने तथा परियोजनाओं में ज्यादा बजट देने की मांग बुलंद की तथा निजीकरण का विरोध किया। अगर सरकार इनकी मांगों पर विचार नहीं करेगी, तो भविष्य में ये परियोजना वर्करों के संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। इसके साथ-साथ उन्होंने 30 जनवरी को होने वाले देशव्यापी जेल भरो आन्दोलन का समर्थन करते हुए इसमें शामिल होने का आह्वान किया।

सभा व प्रदर्शन को सीटू की तरफ से प्रेम देवी, दर्शना व सुदेश रिवासा और एआईयूटीयूसी की तरफ मीरा, पूजा, राजबाला और लक्ष्मी ने भी सम्बोधित किया।

जोरदार नारे लगाते हुए जुलूस नेहरू पार्क से घंटाघर सराय चोपटा के रास्ते रोहतक गेट तक पहुंचा।

दिल्ली: हड़ताल के दिन संयुक्त जुलूस निकालते हुई स्कीम वर्कर

दिल्ली: विरोध प्रदर्शन करते हुए स्कीम वर्कर

भिवानी : सड़कों पर उतरे स्कीम वर्कर

रोहतक: सभा को सम्बोधित करते हुए पुष्पा दलाल

ज्वलंत मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे निर्माण श्रमिक

हिसार (हरियाणा) : पंजीकरण और हितलाभों से जुड़ी समस्याओं को उठाते हुए 16 दिसम्बर को 5 जिलों, हिसार, भिवानी, जींद, फतेहाबाद व सिरसा के सैकड़ों भवन निर्माण कारीगर मजदूरों ने हिसार कमिश्नरी पर प्रदर्शन किया। उन्होंने क्रान्तिमान पार्क से हिसार कमिश्नरी तक जुलूस निकाला और अधिकारी की मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसका नेतृत्व एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा के उपाध्यक्ष कॉ. धर्मवीर सिंह, कोषाध्यक्ष कॉ. राजकुमार जांगड़ा और इंटक, एटक, एचएमएस, बीएमएस आदि से सम्बद्ध अन्य यूनियनों के नेताओं ने किया।

हिसार : विभिन्न ट्रेड यूनियनों से जुड़ी भवन निर्माण श्रमिक यूनियनों द्वारा की गई संयुक्त सभा को सम्बोधित करते हुए एआईयूटीयूसी से संबंधित भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन के राज्य उपाध्यक्ष कॉ. धर्मवीर सिंह

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."

Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com

फोन नं. : 011-25726631, 9868350503